RACE IAS

A Leading Institute For Civil Services Examinations

ANSWERS & EXPLANATIONS

GENERAL STUDIES (P) 2025

TEST 24 : GS FULL LENGTH

EXAM DATE : 03-05-2025

QUESTIONS BOOKLET NO. : 8123472524

1. Answer A

Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DAJGUA):

- It is an umbrella scheme to implement existing schemes across 63,000 Scheduled Tribe-majority villages. Hence, statement 1 is not correct.
    - Dharti Aaba refers to Birsa Munda, a 19th-century tribal leader and anti-colonial icon from Jharkhand. Hence, statement 2 is not correct.

The initiative aims to address critical gaps in social infrastructure, health, education, and livelihood through 25 interventions implemented by various 17 Ministries and Departments of the Government of India. Hence, statement 3 is correct.

2. Answer A
    - The Assam Accord, signed in 1985, was a tripartite agreement between the Central Government, the Assam State Government, and leaders of the Assam Movement, aimed at stopping the influx of illegal migrants from Bangladesh.
        - It led to the introduction of Section 6A into the Citizenship Act, of 1955, exclusively for Assam. Hence, statement 1 is correct.

The committee was chaired by retired Assam High Court Justice Biplab Kumar Sarma and included judges, retired bureaucrats, writers, AASU leaders, and journalists. Hence, statement 2 is not correct.

3. Answer A
    - FDI in the Defence sector is allowed up to 74% through Automatic Route (from earlier 49%) for companies seeking new industrial licenses. Hence, statement 1 is not correct.
    - Further, 100% FDI in the Telecom Sector is allowed under the Automatic Route. Hence, statement 2 is not correct.
    - FDI sectoral cap in the insurance sector has been revised from 49% to 74% under the automatic route. The Union Budget 2025 also announced the further increase of FDI sectoral cap for the insurance sector from 74% to 100%. This enhanced limit will be available for those companies, which invest the entire premium in India.Hence, statement 3 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

1. उत्तर A

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA):

- यह 63,000 अनुसूचित जनजाति-बहुल गांवों में मौजूदा योजनाओं को लागू करने के लिए एक छत्र योजना है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
    - धरती आबा झारखंड के 19वीं सदी के आदिवासी नेता और उपनिवेशवाद विरोधी प्रतीक बिरसा मुंडा को संदर्भित करता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। इसलिए, कथन 3 सही है।

2. उत्तर A
    - 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की आमद को रोकना था।
    - इसने नागरिकता अधिनियम, 1955 में असम के लिए विशेष रूप से धारा 6A की शुरुआत की। इसलिए, कथन 1 सही है।
    - समिति की अध्यक्षता असम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिप्लब कुमार सरमा ने की और इसमें न्यायाधीश, सेवानिवृत्त नौकरशाह, लेखक, AASU नेता और पत्रकार शामिल थे। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

3. उत्तर A

नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (पहले 49% से) के माध्यम से 74% तक एफडीआई की अनुमति है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

इसके अलावा, दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई क्षेत्रीय सीमा को स्वचालित मार्ग के तहत 49% से संशोधित कर 74% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई क्षेत्रीय सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की भी घोषणा की गई। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी, जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। इसलिए, कथन 3 सही है।

ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH, LUCKNOW & KANPUR
WEBSITE :www.raceias.com, /raceiaslucknow
E-mail ID : www.raceias.2010@gmail.com
8917851448
MOCK TEST EXPLANATIONS
RACE IAS

4. Answer A
   - The scheme provides insurance coverage under the PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM Suraksha Bima Yojana for enrolled candidates. Hence, statement 1 is correct.
   - Graduates from premier institutions like IITs, IIMs, and those with professional qualifications such as Chartered Accountants (CA) are excluded from the scheme. Hence, statement 2 is not correct.
   - The scheme is only available to candidates whose family income does not exceed Rs.8 lakh annually, and families with government employees are ineligible. Hence, statement 3 is correct.

5. Answer D
   - India, the world's 3rd-largest oil importer and consumer, relies on imports for over 85% of its crude needs. With primary energy demand set to nearly double to 1,123 million tonnes of oil equivalent by 2040 driven by a projected Gross Domestic Product (GDP) rise to USD 8.6 trillion, making supply stability crucial. Hence, statement 1 is correct.
   - India aims to double its oil & gas exploration area from 0.5 million sq. km by 2025 to 1 million sq. km by 2030. Hence, statement 2 is correct.
   - The Ethanol Blended Petrol (EBP) programme has reduced CO_2 emissions by 544 lakh metric tons and substituted 181 lakh metric tons of crude oil. Hence, statement 3 is correct.

6. Answer B
   - The Beijing Declaration and Platform for Action (1995) was adopted at the 4th World Conference on Women, held in Beijing, China, in 1995. Hence, statement 1 is not correct.
   - Beijing+30 Action Agenda: It marks the 30th anniversary (1995-2025) of the BPfA to review and appraise its implementation. Hence, statement 2 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

4. उत्तर A
   - यह योजना नामांकित उम्मीदवारों के लिए पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसलिए, कथन 1 सही है।
   - आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) जैसी पेशेवर योग्यता वाले लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
   - यह योजना केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिनके परिवार की आय सालाना 8 लाख रुपये से अधिक नहीं है, और सरकारी कर्मचारियों वाले परिवार अपात्र हैं। इसलिए, कथन 3 सही है।

5. उत्तर D
   - भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है, जो अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल की ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर करता है। अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने से 2040 तक प्राथमिक ऊर्जा मांग लगभग दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन तेल के बराबर हो जाएगी, जिससे आपूर्ति स्थिरता महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए, कथन 1 सही है।
   - भारत का लक्ष्य 2025 तक अपने तेल और गैस अन्वेषण क्षेत्र को 0.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 2030 तक 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर करना है। इसलिए, कथन 2 सही है।
   - इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम ने CO_2 उत्सर्जन में 544 लाख मीट्रिक टन की कमी की है और 181 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विकल्प दिया है। इसलिए, कथन 3 सही है।

6. उत्तर B

बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के लिए मंच (1995) को 1995 में बीजिंग, चीन में आयोजित महिलाओं पर 4 वें विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

बीजिंग + 30 एक्शन एजेंडा: यह BPFA की 30 वीं वर्षगांठ (1995-2025) को इसके कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए चिह्नित करता है। इसलिए, कथन 2 सही है।

7. Answer B
   - The proceeds are not exclusively allocated to renewable energy projects; they can also fund initiatives like energy efficiency, clean transportation, and sustainable agriculture. Hence, statement 1 is not correct.
   - Green bonds in India are regulated by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), which introduced a framework for their issuance and listing in 2017. Hence, statement 2 is correct.

8. Answer A
   - LEDs operate on the principle of electroluminescence, where light is emitted when an electric current passes through a semiconductor material, causing electrons and holes to recombine and release energy in the form of photons (light). Hence, statement 1 is correct.
   - LEDs are more energy-efficient than incandescent and fluorescent bulbs because they convert a higher percentage of electricity into light, generating less heat, and have a higher luminous efficacy, meaning they produce more light per unit of energy used. Hence, statement 2 is correct.
   - LED bulbs are mercury-free, unlike fluorescent bulbs that contain mercury. LEDs are a safer alternative to fluorescent and CFL bulbs, which contain mercury. This makes LEDs not only energy-efficient but also eco-friendly. Hence, statement 3 is not correct.

9. Answer A

   A US company, Firefly Aerospace, successfully landed its Blue Ghost Mission 1 on the Moon, marking the 2nd private lunar landing and the 1st to land upright.

   The mission is nicknamed “Ghost Riders in the Sky” and was launched in January 2025 aboard a SpaceX Falcon 9 rocket.

   It landed (lander name: Golden) near Mons Latreille, a volcanic formation on the Moon’s northeastern near side.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

7. उत्तर B

आय को विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित नहीं किया जाता है; वे ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन और टिकाऊ कृषि जैसी पहलों को भी निधि दे सकते हैं। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

भारत में ग्रीन बॉन्ड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसने 2017 में उनके जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए एक रूपरेखा पेश की। इसलिए, कथन 2 सही है।

8. उत्तर A
   - एलईडी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं, जहां अर्धचालक पदार्थ से विद्युत धारा गुजरने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और छिद्र पुनः संयोजित होते हैं और फोटॉन (प्रकाश) के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। इसलिए, कथन 1 सही है।
   - एलईडी तापदीप्त और फ्लोरोसेंट बल्बों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल हैं क्योंकि वे बिजली के उच्च प्रतिशत को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं, कम गर्मी पैदा करते हैं, और उनकी चमकदार प्रभावकारिता अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि वे उपयोग की गई ऊर्जा की प्रति इकाई अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसलिए, कथन 2 सही है।
   - एलईडी बल्ब पारा मुक्त होते हैं, फ्लोरोसेंट बल्बों के विपरीत जिनमें पारा होता है। एलईडी फ्लोरोसेंट और सीएफएल बल्बों के लिए एक सुरक्षित विकल्प हैं, जिनमें पारा होता है। यह एलईडी को न केवल ऊर्जा-कुशल बनाता है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी बनाता है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

9. उत्तर A

एक अमेरिकी कंपनी, फायरफ्लाई एयरोस्पेस ने अपने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा, जो कि दूसरी निजी चंद्र लैंडिंग और सीधा उतरने वाला पहला मिशन था।

इस मिशन का उपनाम "घोस्ट राइडर्स इन द स्काई" है और इसे जनवरी 2025 में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था।

यह चंद्रमा के उत्तरपूर्वी निकटवर्ती भाग पर एक ज्वालामुखी संरचना मॉन्स लैट्रेइल के पास उतरा (लैंडर का नाम: गोल्डन)।

10. Answer B

India (Jaipur, Rajasthan) hosted the 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and the Pacific emphasising on sustainable waste management and circular economy. Hence, statement 1 is not correct.

It is a regional platform that promotes 3R (Reduce, Reuse, Recycle) principles and circular economy practices across the Asia-Pacific region. Hence, statement 2 is correct.

Historical Context: Regional 3R and Circular Economy Forum was launched in 2009 to promote 3R principles and resource efficiency. The Hanoi 3R Declaration (2013-2023) set 33 voluntary goals for a resource-efficient and circular economy. Hence, statement 3 is correct.

11. Answer A

It aims to combat climate change and limit global warming to well below 2°C above pre-industrial levels, with an ambition to limit warming to 1.5°C. Hence, statement 1 is correct.

It replaced the Kyoto Protocol which was an earlier agreement to deal with climate change. Hence, statement 2 is not correct

Under the Paris Agreement, each country is required to submit and update their NDCs every 5 years, outlining their plans for reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change. Hence, statement 3 is not correct.

12. Answer A

The Wallace Line is an imaginary boundary separating the distinct faunal regions of Asia and Australia.

13. Answer C

The Blue Box is essentially an "Amber Box with conditions", where subsidies that would typically fall under the Amber Box are allowed in Blue box if they require farmers to limit production (as specified in Paragraph 5 of Article 6 of the WTO Agriculture Agreement). Hence, statement 1 is correct.

Currently, there are no spending limits on Blue Box subsidies. Hence, statement 2 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

10. उत्तर B

भारत (जयपुर, राजस्थान) ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की, जिसमें टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

यह एक क्षेत्रीय मंच है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 3R (कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें) सिद्धांतों और परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इसलिए, कथन 2 सही है। ऐतिहासिक संदर्भ: 3R सिद्धांतों और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 2009 में क्षेत्रीय 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच शुरू किया गया था। हनोई 3R घोषणा (2013-2023) ने संसाधन-कुशल और परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए 33 स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित किए। इसलिए, कथन 3 सही है

11. उत्तर A

इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, साथ ही वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की महत्वाकांक्षा है। इसलिए, कथन 1 सही है।

इसने क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ली जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पुराना समझौता था। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है

पेरिस समझौते के तहत, प्रत्येक देश को हर 5 साल में अपने एनडीसी प्रस्तुत करने और उन्हें अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की उनकी योजनाओं की रूपरेखा होती है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

12. उत्तर A

वैलेस रेखा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अलग-अलग जीव-जंतुओं के क्षेत्रों को अलग करने वाली एक काल्पनिक सीमा है।

13. उत्तर C

ब्लू बॉक्स अनिवार्य रूप से एक "शर्तों वाला एम्बर बॉक्स" है, जहाँ सब्सिडी जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आती है, उसे ब्लू बॉक्स में अनुमति दी जाती है यदि वे किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है (जैसा कि WTO कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट है)। इसलिए, कथन 1 सही है।

वर्तमान में, ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर कोई खर्च सीमा नहीं है। इसलिए, कथन 2 सही है।

14. Answer B

Position in Global Textile Trade: India has the 2nd largest textile manufacturing capacity globally and ranks as the 6th largest exporter of textiles and apparel in 2023 (accounting for 3.9% of global trade). Hence, statement 1 is correct.

India is the largest producer of jute in the world, and 2nd largest producer of man-made fibres (MMF), including polyester, viscose, nylon, and acrylic. Hence, statement 2 is correct.

100% Foreign Direct Investment (FDI) allowed in the textile sector under the automatic route to attract foreign investment. Hence, statement 3 is not correct.

15. Answer C

- The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) was established as an autonomous body in 1942, to address the needs of industrial research in the country. Further, evolving the scope and range of activities in several domains, CSIR today is known for its excellence in research and development and science and technology innovations.
- It is the country's custodian for measurement standards of mass, distance, time, temperature, current, etc. Hence statement 1 is correct.
- CSIR has created and is the custodian of Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) which is a powerful weapon against unethical commercial exploitation of Indian traditional knowledge. Pioneer of India's intellectual property movement, CSIR is strengthening its patent portfolio to carve out global niches for the country in select technology domains. Hence statement 2 is correct.

16. Answer B

Unnat Bharat Abhiyan is a flagship program of the Ministry for Human Resource Development (MHRD). It aims to connect the Higher Education Institutions with a set of at least five villages or local communities to address development challenges through appropriate technologies so that these institutions can contribute to the economic and social betterment of these village communities using their knowledge base.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

14. उत्तर B

वैश्विक कपड़ा व्यापार में स्थिति: भारत में वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी कपड़ा विनिर्माण क्षमता है और 2023 में कपड़ा और परिधान का 6वाँ सबसे बड़ा निर्यातक है (वैश्विक व्यापार का 3.9% हिस्सा)। इसलिए, कथन 1 सही है।

भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और पॉलिएस्टर, विस्कोस, नायलॉन और ऐक्रेलिक सहित मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसलिए, कथन 2 सही है।

विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्वचालित मार्ग के तहत कपड़ा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

15. उत्तर C

- देश में औद्योगिक अनुसंधान की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1942 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इसके अलावा, कई डोमेन में गतिविधियों के दायरे और सीमा को विकसित करते हुए, CSIR आज अनुसंधान और विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है।
- यह द्रव्यमान, दूरी, समय, तापमान, वर्तमान आदि के माप मानकों के लिए देश का संरक्षक है। इसलिए कथन 1 सही है।
- सीएसआईआर ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) बनाई है और इसका संरक्षक है जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनैतिक वाणिज्यिक शोषण के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है। भारत के बौद्धिक संपदा आंदोलन के अग्रणी, सीएसआईआर चुनिंदा प्रौद्योगिकी डोमेन में देश के लिए वैश्विक स्थान बनाने के लिए अपने पेटेंट पोर्टफोलियो को मजबूत कर रहा है। इसलिए कथन 2 सही है।

16ए उत्तर B

उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को उचित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए कम से कम पाँच गाँवों या स्थानीय समुदायों के समूह से जोड़ना है ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार का उपयोग करके इन गाँव समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें।

17. Answer D

- India currently harbors almost 75% of the world's wild tiger population. The recently concluded tiger census declared the minimum tiger population of 3167, which is the population estimate from the camera-trapped area. Now, further analysis of data, done by the Wildlife Institute of India, from both camera-trapped and non-camera-trapped tiger presence areas, the upper limit of the tiger population is estimated to be 3925 and the
- average number is 3682 tigers, reflecting a commendable annual growth rate of 6.1%per annum. Hence statement 1 is not correct.
- The tiger abundance within the Tiger Reserve is highest in Corbett (260), followed by Bandipur (150),Nagarhole (141), Bandhavgarh (135), Dudhwa (135), Mudumalai(114), Kanha (105), Kaziranga (104),Sundarbans (100), Tadoba (97), Sathyamangalam (85), and Pench-MP (77). Hence statement 2 is not correct.
- The largest tiger population of 785 is in Madhya Pradesh, followed by Karnataka (563) & Uttarakhand (560), and Maharashtra (444).
- The National Tiger Conservation Authority and Wildlife Institute of India with support from respective state forest departments conducts a tiger census once every 4 years. Hence statement 3 is not correct

17. उत्तर D

- भारत में वर्तमान में दुनिया की जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% हिस्सा है। हाल ही में संपन्न बाघ जनगणना ने न्यूनतम बाघ आबादी 3167 घोषित की, जो कैमरा-ट्रैप्ड क्षेत्र से जनसंख्या का अनुमान है। अब, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा कैमरा-ट्रैप्ड और गैर-कैमरा-ट्रैप्ड बाघ उपस्थिति क्षेत्रों दोनों से किए गए डेटा के आगे विश्लेषण से, बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा 3925 होने का अनुमान है और
- औसत संख्या 3682 बाघ हैं, जो प्रति वर्ष 6.1% की सराहनीय वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की बहुतायत कॉर्बेट (260) में सबसे अधिक है, इसके बाद बांदीपुर (150), नागरहोल (141), बांधवगढ़ (135), दुधवा (135), मुदुमलाई (114), कान्हा (105), काजीरंगा (104), सुंदरबन (100), ताडोबा (97), सत्यमंगलम (85), और पेंच-एमपी (77) हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
- सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या 785 मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक (563) और उत्तराखंड (560) और महाराष्ट्र (444) का स्थान है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान संबंधित राज्य वन विभागों के सहयोग से हर 4 साल में एक बार बाघों की जनगणना करते हैं। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

18. Answer A

- The National Centre for Good Governance (NCGG) traces its origin to the National Institute of Administrative Research (NIAR), which was set up in 1995 by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), the Government of India's topmost training institute for civil services, but it was set up in 2014. NIAR was subsequently rechristened and subsumed into NCGG. Hence statement 1 is not correct.
- The National Centre for Good Governance (NCGG) was set up in 2014 by the Government of India as an apex–level autonomous institution under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. NCGG deals with a gamut of governance issues from local, state to national levels, across all sectors. Hence statement 2 is not correct.
- The Centre is mandated to work in the areas of governance, policy reforms, capacity building and training of civil servants and technocrats of India and other developing countries. It also offers training programs for civil servants from other countries as part of India's soft power diplomacy. The two-week-long 71st batch Capacity Building Programme
- (CBP) for the civil servants of Bangladesh organised by the National Centre for Good Governance (NCGG) in partnership with the
- Ministry of External Affairs (MEA) concluded on 15th March 2024. Following the completion of the first phase of CBP for 1,500 civil servants, NCGG signed an MoU with the Government of Bangladesh to enhance the capacity of an additional 1,800 civil servants by 2025. Hence statement 3 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

18. उत्तर A

- राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) की उत्पत्ति राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (NIAR) से हुई है, जिसे 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) द्वारा स्थापित किया गया था, जो भारत सरकार का सिविल सेवाओं के लिए सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है, लेकिन इसे 2014 में स्थापित किया गया था। NIAR को बाद में पुनः नामांकित किया गया और NCGG में शामिल कर लिया गया। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) की स्थापना 2014 में भारत सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष-स्तरीय स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। एनसीजीजी सभी क्षेत्रों में स्थानीय, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शासन के मुद्दों से निपटता है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
- केंद्र को भारत और अन्य विकासशील देशों के सिविल सेवकों और टेक्नोक्रेटों के शासन, नीति सुधार, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में काम करने का अधिकार है। यह भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के हिस्से के रूप में अन्य देशों के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है।
- विदेश मंत्रालय (MEA) के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) द्वारा आयोजित बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए दो सप्ताह तक चलने वाला 71वां बैच क्षमता निर्माण कार्यक्रम (CBP) 15 मार्च 2024 को संपन्न हुआ।
- 1,500 सिविल सेवकों के लिए CBP के पहले चरण के पूरा होने के बाद, NCGG ने 2025 तक अतिरिक्त 1,800 सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अतः कथन 3 सही है।

19. Answer B

- At a more immediate level, the DoPT is directly responsible for being the cadre controlling authority for the IAS and the three secretariat services in the Central Secretariat. The Department also operates the Central Staffing Scheme under which suitable officers from All India Services and Group 'A' Central Services are selected and then placed in posts at the level of Deputy Secretary/Director and Joint Secretary, on the basis of tenure deputation. The Department also deals with cases of appointment to posts of Chairman, Managing Director, and full-time functional Director/member of the board of management of various public sector undertakings/enterprises, corporations, banks and financial institutions. Hence, statements 1 and 2 are correct.
- It also deals with the assignment of Indian experts to various developing countries. It is also responsible for the formulation and coordination of training policies for the All India and Central Services and providing support for the capacity building of state government officials. Hence, statement 3 is not correct.

20. Answer D

- The National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) aims to promote apprenticeship training in the country, by providing partial stipend support to the apprentices engaged under the Apprentice Act,1961, undertaking capacity building of the apprenticeship ecosystem, and providing advocacy assistance to the stakeholders. Hence, statement 1 is not correct.
- The beneficiaries of the scheme include all categories of apprentices except Graduate, Technician, and Technician (Vocational) apprentices. Hence, statement 2 is not correct.

19. उत्तर बी

- अधिक तात्कालिक स्तर पर, डीओपीटी केंद्रीय सचिवालय में आईएएस और तीन सचिवालय सेवाओं के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण होने के लिए सीधे जिम्मेदार है। विभाग केंद्रीय स्टाफिंग योजना भी संचालित करता है जिसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं और समूह 'ए' केंद्रीय सेवाओं के उपयुक्त अधिकारियों का चयन किया जाता है और फिर उन्हें कार्यकाल प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप सचिव/निदेशक और संयुक्त सचिव के स्तर पर पदों पर रखा जाता है। विभाग विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों, निगमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक/सदस्य के पदों पर नियुक्ति के मामलों को भी देखता है। इसलिए, कथन 1 और 2 सही हैं।
- यह विभिन्न विकासशील देशों में भारतीय विशेषज्ञों की नियुक्ति से भी संबंधित है। यह अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण नीतियों के निर्माण और समन्वय और राज्य सरकार के अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

20. उत्तर D

- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) का उद्देश्य प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत लगे प्रशिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करके, प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता निर्माण का कार्य करके और हितधारकों को वकालत सहायता प्रदान करके देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- योजना के लाभार्थियों में स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं को छोड़कर सभी श्रेणियां शामिल हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

21. Answer C
- The state of Gujarat shares 5 percent of the country's population and it shares 19.5 percent of national agriculture production. It harvests cotton, groundnut, rice ,bajra, maize as Kharif crops and wheat, gram,mustard, cumin as Rabi crops. The production of foodgrains is estimated at 108.15 lakh tonnes and production of cotton is estimated at 73.88 lakh bales. Gujarat is first in cotton and groundnut production. Hence statement 1 is correct.
- The state of Madhya Pradesh posted the country's highest agricultural growth rate which averaged above 20 percent over the last four years. The state leads the country in production of pulses, oilseeds,soybean and black gram. The state is second in the country in production of wheat, red lentils, maize and sesame. Horticulture is being promoted in a big way. According to Economic Survey 2022-23, Madhya Pradesh produced around 21% (highest share) of total pulses in India. Hence statement 2 is correct.
- Coconut is the only major crop with a production of 60 million nuts per year. Lakshadweep coconut is branded as an organic product. In India, Lakshadweep stands first in coconut production and productivity per hectare is 20,600 and average yield per palm per year is 82 coconuts. The Lakshadweep coconuts are the highest oil content nuts in the world (82 per cent). Hence statement 3 is correct.

22. Answer C
- PRAAPTI (Payment Ratification And Analysis in Power Procurement for Bringing Transparency in Invoicing of Generators) is a platform aimed at enhancing transparency and encouraging best practices in power purchase transactions.
- Launched in 2018 by the Ministry of Power, PRAAPTI allows power distribution companies to clear invoices and respond to claims raised by generators.
  The platform captures invoicing and payment data from generators for various long-term Power Purchase Agreements (PPAs).

21. उत्तर C
- गुजरात राज्य देश की आबादी का 5 प्रतिशत हिस्सा है और यह राष्ट्रीय कृषि उत्पादन का 19.5 प्रतिशत हिस्सा साझा करता है। यह खरीफ फसलों के रूप में कपास, मूंगफली, चावल, बाजरा, मक्का और रबी फसलों के रूप में गेहूं, चना, सरसों, जीरा की फसल लेता है। खाद्यान्न का उत्पादन 108.15 लाख टन और कपास का उत्पादन 73.88 लाख गांठ होने का अनुमान है। गुजरात कपास और मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसलिए कथन 1 सही है।
- मध्य प्रदेश राज्य ने देश की सबसे अधिक कृषि विकास दर दर्ज की, जो पिछले चार वर्षों में औसतन 20 प्रतिशत से अधिक रही। दलहन, तिलहन, सोयाबीन और काले चने के उत्पादन में राज्य देश में अग्रणी है। गेहूं, लाल मसूर, मक्का और तिल के उत्पादन में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। बागवानी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, मध्य प्रदेश ने भारत में कुल दालों का लगभग 21% (उच्चतम हिस्सा) उत्पादन किया। अतः कथन 2 सही है।
- नारियल एकमात्र प्रमुख फसल है जिसका उत्पादन प्रति वर्ष 60 मिलियन नट्स का होता है। लक्षद्वीप नारियल को जैविक उत्पाद के रूप में ब्रांड किया गया है। भारत में, लक्षद्वीप नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 20,600 है

22. उत्तर C
- PRAAPTI (जनरेटर के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद में भुगतान अनुसमर्थन और विश्लेषण) एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य बिजली खरीद लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया, PRAAPTI बिजली वितरण कंपनियों को चालान साफ़ करने और जनरेटर द्वारा उठाए गए दावों का जवाब देने की अनुमति देता है

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

23. Answer C

- Procurement of these commodities is undertaken by Central Nodal agencies at the Minimum Support Price (MSP) announced by the Government. Hence, pair 1 is correctly matched.
- PDPS: - This scheme envisages direct payment of the difference between the MSP and the selling /modal price to pre-registered farmers selling their produce in the notified market yard through a transparent auction process. All the payments will be transferred directly into the bank account of farmers. This scheme does not involve any physical procurement of crops. Hence, pair 2 is correctly matched.
- PPSS: - In addition to PDPS, oilseed-producing States will have the option to roll out a Private Procurement Stockist Scheme (PPSS) on a pilot basis in district/ selected APMC(s) of the district involving the participation of private stockists. The pilot district/ selected APMC(s) of the district will cover one or more crops of oilseeds for which MSP is notified. This scheme allows private entities, including processors and exporters, to procure agricultural produce directly from farmers at MSPs, with the government providing financial support to ensure procurement at MSPs. Hence, pair 3 is correctly matched.

24. Answer B

The scheme aims to provide an environment for socio-economic upliftment and overall development of the Scheduled Castes (SCs) by providing financial assistance to the best private residential schools affiliated by CBSE/ State Board in class 9th & 11th for completion of education till 12th standard. Hence statement (b) is not correct. Further, financial assistance is also provided to Non-Governmental Organisations (NGOs)/ Voluntary Organisations (VOs) for running residential, and non-residential schools and hostels that have adequate infrastructure and maintain good academic quality for SC students.

23. उत्तर सी

- इन वस्तुओं की खरीद सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाती है। इसलिए, युग्म 1 सही ढंग से सुमेलित है।
- पीडीपीएस: - इस योजना में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व-पंजीकृत किसानों को एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान करने की परिकल्पना की गई है। सभी भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। इस योजना में फसलों की कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है। इसलिए, जोड़ी 2 सही ढंग से सुमेलित है।
- पीपीएसएस: - पीडीपीएस के अलावा, तिलहन उत्पादक राज्यों के पास निजी स्टॉकिस्टों की भागीदारी को शामिल करते हुए जिले/जिले के चयनित एपीएमसी में पायलट आधार पर निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) शुरू करने का विकल्प होगा। जिले के पायलट जिले/चयनित एपीएमसी में तिलहन की एक या अधिक फसलों को कवर किया जाएगा, जिनके लिए एमएसपी अधिसूचित है। यह योजना प्रोसेसर और निर्यातकों सहित निजी संस्थाओं को एमएसपी पर किसानों से सीधे कृषि उपज खरीदने की अनुमति देती है

24. उत्तर B

इस योजना का उद्देश्य 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में सीबीएसई/राज्य बोर्ड से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जातियों (एससी) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। इसलिए कथन (b) सही नहीं है। इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) को आवासीय और गैर-आवासीय स्कूलों और छात्रावासों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिनमें पर्याप्त बुनियादी ढांचा होता है और जो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अच्छी शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखते हैं।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

25. Answer C
- PM MITRA Scheme: PM MITRA Park will be developed by a Special Purpose Vehicle
- (SPV) which will be owned by the Central and State Government and in a Public Private Partnership (PPP) Mode. Hence statement 1 is correct.
- State governments will provide a contiguous and encumbrance-free land parcel of at least 1000 acres of land for the park. Hence statement 2 is correct.

26. Answer B

The Ministry of Coal (MoC) has developed a National Lignite Index (NLI) for facilitating auction of lignite mines on a revenue-share basis. In order to arrive at the revenue share based on market prices of Lignite, National Lignite Index (NLI) has been conceptualized. The concept and design of the Index as well as the Base Prices have been developed by the Indian Statistical Institute, Kolkata. Hence statement 1 is not correct.

27. Answer C
- The Victoria Memorial Hall (VMH), Kolkata was founded principally through the efforts of Viceroy Lord Curzon, in 1921 as a period museum in the memory of Queen Victoria with particular emphasis on Indo-British history. Hence statement 1 is correct.
- The VMH was declared an institution of national importance by the Government of India Act of 1935. Hence statement 2 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

25. उत्तर C
- पीएम मित्र योजना: पीएम मित्र पार्क को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा और यह सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में होगा। इसलिए कथन 1 सही है।
- राज्य सरकारें पार्क के लिए कम से कम 1000 एकड़ भूमि का एक सन्निहित और अतिक्रमण-मुक्त भूमि पार्सल प्रदान करेंगी। इसलिए कथन 2 सही है।

26. उत्तर B

कोयला मंत्रालय (MoC) ने राजस्व-साझाकरण के आधार पर लिग्नाइट खदानों की नीलामी की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक (NLI) विकसित किया है। लिग्नाइट के बाजार मूल्यों के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी पर पहुंचने के लिए, राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक (NLI) की अवधारणा की गई है

27ण उत्तर C
- विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (VMH), कोलकाता की स्थापना मुख्य रूप से वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1921 में महारानी विक्टोरिया की याद में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में की गई थी, जिसमें भारत-ब्रिटिश इतिहास पर विशेष जोर दिया गया था। इसलिए कथन 1 सही है।
- VMH को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। इसलिए कथन 2 सही है।

28. Answer D

- The Pradhan Mantri JI-VAN Yojana is aimed at providing financial support to integrated bio-ethanol projects using biomass and other renewable feedstock, not limited to sugarcane. It focuses on second- generation (2G) bioethanol production, which can be derived from non-food feedstocks such as agricultural residues, and municipal solid waste. Hence statement 1 is not correct.

  The scheme's primary focus is on promoting the production of bioethanol, and it may not strictly limit funding to public sector companies alone. Generally, such schemes are designed to encourage both public and private sector participation to achieve their goals. For setting up Commercial projects, the Project Developers

- eligible under the scheme would be State Govt. enterprises, Central Public Sector undertakings & Private Entities as per eligibility criteria under Section 3 i.e. Technical Pre-Qualification Criteria. Hence statement 3 is not correct.

29. Answer D

- In order to ensure sufficient availability in the domestic market as well as proactively monitoring the sugar market to contain the price increases, if any, DGFT, Ministry of Commerce, regulated the exports of sugar from June 2022 under which Directorate of Sugar, Department of Food and Public Distribution will issue export release orders to exporters of sugar and sugar mills. Hence statement 1 is not correct.
- In order to prevent any unnecessary import of sugar and to stabilize the domestic price at a reasonable level, the central government has increased custom duty on import of sugar from 50 to 100 percent in the interest of farmers February 2018. Hence statement 2 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

28. उत्तर D

- प्रधानमंत्री जी-वन योजना का उद्देश्य बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो गन्ने तक सीमित नहीं है। यह दूसरी पीढ़ी (2G) बायोइथेनॉल उत्पादन पर केंद्रित है, जिसे कृषि अवशेषों और नगरपालिका के ठोस कचरे जैसे गैर-खाद्य फीडस्टॉक से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- योजना का प्राथमिक ध्यान बायोइथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने पर है, और यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ही वित्त पोषण को सख्ती से सीमित नहीं कर सकता है। आम तौर पर, ऐसी योजनाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए, इस योजना के तहत पात्र परियोजना डेवलपर्स राज्य सरकार के उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी संस्थाएँ होंगी, जो धारा 3 के तहत पात्रता मानदंड यानी तकनीकी पूर्व-योग्यता मानदंड के अनुसार होंगी। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

29. उत्तर D

- घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो, को नियंत्रित करने के लिए चीनी बाजार की सक्रिय निगरानी करने के लिए, वाणिज्य मंत्रालय के DGFT ने जून 2022 से चीनी के निर्यात को विनियमित किया, जिसके तहत चीनी निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग चीनी और चीनी मिलों के निर्यातकों को निर्यात रिलीज आदेश जारी करेगा। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- चीनी के किसी भी अनावश्यक आयात को रोकने और घरेलू मूल्य को उचित स्तर पर स्थिर करने के लिए, केंद्र सरकार ने फरवरी 2018 में किसानों के हित में चीनी के आयात पर सीमा शुल्क 50 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

30. Answer D

- The National Calendar based on the Saka Era, with Chaitra as its first month and a normal year of 365 days was adopted from March 22, 1957 along with the Gregorian calendar for the following official purposes:
  - Gazette of India
  - news broadcast by All India Radio,
  - calendars issued by the Government of India and
  - Government communications addressed to the public. Hence, statement 1 is not correct.
- Dates of the National Calendar have a permanent correspondence with dates of the Gregorian Calendar, 1 Chaitra falling on March 22 normally and on March 21 in leap year. Hence, statement 2 is not correct.

31. Answer A

The Unani System of Medicine came to India in the eighth century and developed as a comprehensive medical system. It has been practiced, taught and scientifically documented in different parts of the country and flourished as a scientific medical system. With its wide network of quality educational institutions, comprehensive healthcare facilities, state-of-the-art research institutions and quality drug manufacturing industries and on account of its utilisation by a large number of people for their healthcare needs, India has emerged as the global leader in Unani System of Medicine. Hence statement 3 is not correct.

32. Answer B

- 'SATAT' (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) scheme on Compressed biogas (CBG) was launched by the Hon'ble Minister of Petroleum & Natural Gas on 1.10.2018.
- The scheme envisages to target production of 15 MMT (million tons) of CBG by 2023, from 5000 Plants. Hence statement 2 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

30. उत्तर D

- शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का है, को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च, 1957 से निम्नलिखित आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था:
  - भारत का राजपत्र
- ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार,
- भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और
- जनता को संबोधित सरकारी संचार। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी रूप से मेल खाती हैं, 1 चैत्र सामान्य रूप से 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

31. उत्तर A

यूनानी चिकित्सा पद्धति आठवीं शताब्दी में भारत आई और एक व्यापक चिकित्सा प्रणाली के रूप में विकसित हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में इसका अभ्यास, शिक्षण और वैज्ञानिक रूप से दस्तावेजीकरण किया गया है और यह एक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों, व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं, अत्याधुनिक अनुसंधान संस्थानों और गुणवत्तापूर्ण दवा निर्माण उद्योगों के अपने व्यापक नेटवर्क के साथ और बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अपनी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के लिए इसके उपयोग के कारण, भारत यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

32. उत्तर B

संपीड़ित बायोगैस (CBG) पर 'SATAT' (सस्ती परिवहन के लिए सतत विकल्प) योजना 1.10.2018 को माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना में 5000 संयंत्रों से 2023 तक 15 MMT (मिलियन टन) CBG के उत्पादन को लक्षित करने की परिकल्पना की गई है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

33. Answer C
- Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System (CPGRAMS) is an online web-enabled system over NICNET developed by National Informatics Centre (NIC), in association with the Directorate of Public Grievances (DPG) and the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG). It is designed to facilitate the online lodging of grievances by citizens and to monitor their redressal by various governmental organizations. Hence statement 1 is correct.
- CPGRAMS provides a facility for users to track the status of their grievances in real time. The CPGRAMS portal offers users the ability to track the progress of their grievances, providing transparency and ensuring accountability in the grievance redressal process. Hence statement 2 is correct.
- CPGRAMS is designed to address grievances related to service delivery by the government and its agencies. Issues which are not taken up for redress:
  - RTI Matters. Hence statement 3 is correct.
  - Court-related / Subjudice matters

34. Answer C
- India's share in global ship repair is less than 1 percent, the country's location is favorable with 7-9 percent of the global trade passing within 300 nautical miles of the coastline.
- Amongst public sector dockyards, Cochin Shipyard Ltd. has the highest capacity for ship repairing (125 deadweight tonnage). Hence statement 1 is correct.
- Cochin Shipyard Ltd (CSL) is the largest shipbuilding and maintenance facility in India. Hence statement 2 is correct.
- India acceded to the Hong Kong International Convention for environmentally safe and sound recycling of ships (HKC) in 2019. Hence statement 3 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

33. उत्तर C
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) NICNET पर एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा लोक शिकायत निदेशालय (DPG) और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे नागरिकों द्वारा शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने और विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा उनके निवारण की निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
- CPGRAMS उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। CPGRAMS पोर्टल उपयोगकर्ताओं को अपनी शिकायतों की प्रगति को ट्रैक करने, पारदर्शिता प्रदान करने और शिकायत निवारण प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने की क्षमता प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है।
- CPGRAMS को सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सेवा वितरण से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे मुद्दे जिन्हें निवारण के लिए नहीं लिया जाता है:
  - आरटीआई मामले। अतः कथन 3 सही है।
  - न्यायालय से संबंधित / विचाराधीन मामले

34. उत्तर C
- वैश्विक जहाज मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से भी कम है, देश का स्थान अनुकूल है, जहाँ वैश्विक व्यापार का 7-9 प्रतिशत समुद्र तट के 300 समुद्री मील के भीतर से गुजरता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के डॉकयार्डों में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जहाज मरम्मत की सबसे अधिक क्षमता (125 डेडवेट टन भार) है। इसलिए कथन 1 सही है।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) भारत में सबसे बड़ी जहाज निर्माण और रखरखाव सुविधा है। इसलिए कथन 2 सही है।
- भारत ने 2019 में जहाजों के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और स्वस्थ पुनर्चक्रण (एचकेसी) के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। अतः कथन 3 सही है।

35. Answer B
- Different varieties of marble, granite, sandstone and Kota stone. With discovery of oil and natural gas in western Rajasthan, the state has emerged as the second highest producer of crude oil after Bombay High in the country.
- At present about 92,000-93,000 barrels of oil per day is being produced from Oil/Gas Fields of Rajasthan namely Mangla, Bhagyam, Aishwariya, Saraswati, Raageshwari oil, Rageshwari-S1, ABH, Guda, NE, NI, NL, Raag Deep Gas, KW2. Hence statement 2 is not correct.

36. Answer D
- The Forest conservation Act 1980 does not provide for the definition of forest land. At present, in India, there is no clear nationally-accepted definition of 'forest'.
- In September 2019, the Forest Advisory Committee (FAC) observed that there cannot be any uniform criteria to define forest which can be applicable to all forest types in all states and union territories. Hence statement 1 is not correct.
- The amended Act—the Forest (Conservation) Amendment Act (FCAA) of 2023, which received the President's assent in August 2023 after Parliament passed it in July—discards the need to obtain consent from habitation
- level gram sabhas before final forest clearance. Hence statement 2 is not correct.

37. Answer C
- National Livestock Mission intends to achieve the objectives of employment generation through entrepreneurship development in small ruminant, poultry and piggery sector & Fodder sector, increase of per animal productivity through breed improvement, increase in production of meat, egg, goat milk, wool and fodder. Hence statement 1 is correct.
- Under this sub-mission, assistance will be provided to the central Agencies, ICAR Institutes and University farms for applied research required for development of the sector, extension services including promotional activities for animal husbandry and schemes, seminars, conferences, demonstration activities and other IEC activities for awareness generation. Assistance will also be provided for livestock insurance and innovations. Hence statement 2 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations
RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

35. उत्तर B
- संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और कोटा पत्थर की विभिन्न किस्में। पश्चिमी राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के साथ, राज्य देश में बॉम्बे हाई के बाद कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।
- वर्तमान में राजस्थान के तेल/गैस क्षेत्रों मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी तेल, रागेश्वरी-एस1, एबीएच, गुडा, एनई, एनआई, एनएल, राग दीप गैस, केडब्ल्यू2 से प्रतिदिन लगभग 92,000-93,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

36. उत्तर D
- वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन भूमि की परिभाषा प्रदान नहीं करता है। वर्तमान में, भारत में, 'वन' की कोई स्पष्ट राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है।
- सितंबर 2019 में, वन सलाहकार समिति (FAC) ने देखा कि वन को परिभाषित करने के लिए कोई समान मानदंड नहीं हो सकता है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी प्रकार के वनों पर लागू हो सके। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- संशोधित अधिनियम - वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (FCAA) 2023, जिसे जुलाई में संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद अगस्त 2023 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली - अंतिम वन मंज़ूरी से पहले बस्ती स्तर की ग्राम सभाओं से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

37. उत्तर C
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य छोटे जुगाली करने वाले पशुओं, मुर्गी पालन और सूअर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन के उद्देश्यों को प्राप्त करना, नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि, मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसलिए कथन 1 सही है।
- इस उप-मिशन के तहत, क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, पशुपालन और योजनाओं के लिए प्रचार गतिविधियों सहित विस्तार सेवाओं, सेमिनार, सम्मेलनों, प्रदर्शन गतिविधियों और जागरूकता पैदा करने के लिए अन्य आईईसी गतिविधियों के लिए केंद्रीय एजेंसियों, आईसीएआर संस्थानों और विश्वविद्यालय फार्मों को सहायता प्रदान की जाएगी। पशुधन बीमा और नवाचारों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। अतः कथन 2 सही है।

38. Answer A

- Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana - Saubhagya is to provide energy access to all by last mile connectivity and electricity connections to all remaining un-electrified households in rural as well as urban areas to achieve universal household electrification in the country. Hence statement 1 is correct.
- The Rural Electrification Corporation Limited (REC) will remain the nodal agency for the operationalisation of the scheme throughout the country. Hence statement 2 is not correct.

39. Answer B

- Mission Purvodaya in the steel sector is aimed at driving accelerated development of eastern India through the establishment of an integrated steel hub. Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, and northern Andhra Pradesh hold about 80 percent of India's iron ore and nearly all of coking coal.This eastern belt has the potential to add more than 75 percent of the country's incremental steel capacity envisioned by the National Steel Policy. Hence, statement 1 is not correct.

40. Answer D

- Atal Incubation Centre (AIC) programme was launched in 2017 with a vision to build an ecosystem of business incubators where entrepreneurs can gain access to a variety of facilities, including physical infrastructure, training and education, and access to key stakeholders including investors, other innovators, and mentors. Grant up to & 10 crores is given to the AlCs/EICs over a 5-year period.

38. उत्तर A

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य का उद्देश्य देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी शेष अविद्युतीकृत घरों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन द्वारा सभी को ऊर्जा पहुंच प्रदान करना है। इसलिए कथन 1 सही है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी बनी रहेगी। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

39. उत्तर B

इस्पात क्षेत्र में मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति देना है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश में भारत का लगभग 80 प्रतिशत लौह अयस्क और लगभग सभी कोकिंग कोयला है। इस पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय इस्पात नीति द्वारा परिकल्पित देश की वृद्धिशील इस्पात क्षमता का 75 प्रतिशत से अधिक जोड़ने की क्षमता है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

40. उत्तर D

- अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) कार्यक्रम 2017 में बिजनेस इनक्यूबेटरों के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था, जहां उद्यमी भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और शिक्षा सहित विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और निवेशकों, अन्य नवप्रवर्तकों और सलाहकारों सहित प्रमुख हितधारकों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ए.सी./ई.आई.सी. को 5 वर्ष की अवधि में 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

41. Answer C

- The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) is the nodal agency of the Government of India under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions for administrative reforms as well as redressal of public grievances relating to the states in general and those pertaining to central government agencies in particular. The Department endeavors to document and disseminate successful good governance practices by way of audio-visual media and publications. It also undertakes activities in the field of international exchange and cooperation to promote public service reforms. DARPG inter alia, has the responsibility of policy, coordination and monitoring of issues relating to redress of public grievances in general and grievances pertaining to central government agencies, in particular. Hence both statements 1 and 2 are correct.

42. Answer B

- The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) became an Independent Ministry on 15.10.1999 after the merger of the Department of Statistics and the Department of Programme Implementation. The Ministry has two wings, one relating to Statistics and the other to Programme Implementation. MOSPI has been designated as the nodal Ministry to facilitate the implementation of the SAARC Social Charter in India.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

41. उत्तर C

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, जो प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सामान्य रूप से राज्यों से संबंधित और विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण के लिए है। विभाग ऑडियो-विजुअल मीडिया और प्रकाशनों के माध्यम से सफल सुशासन प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और प्रसार करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक सेवा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग के क्षेत्र में गतिविधियाँ भी करता है। डीएआरपीजी के पास अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य रूप से सार्वजनिक शिकायतों और विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित शिकायतों के निवारण से संबंधित मुद्दों की नीति, समन्वय और निगरानी की जिम्मेदारी है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।

42. उत्तर B

- सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) 15.10.1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय बन गया। मंत्रालय के दो विंग हैं, एक सांख्यिकी से संबंधित और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित। भारत में SAARC सामाजिक चार्टर के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए MOSPI को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है।

43. Answer B
- The sub-scheme will be implemented for 4 (four) years from FY 2023-24 to FY 2026-27 across all the States and UTs. Hence, statement 3 is not correct.

44. Answer B
- Tele MANAS will be organized as a two-tier system. Tier 1 will comprise the State Tele MANAS cells, which includes trained counsellors and mental health specialists. Tier 2 will comprise specialists at District Mental Health Programme (DMHP)/Medical College
- resources for physical consultation and/or eSanjeevani for audio visual consultation. Hence statement 1 is not correct

45. Answer B
- The scheme would be run by the Ministry of Women and Child Development under the Sambal sub-scheme of Mission Shakti, which is dedicated to strengthening women's safety, security and empowerment. Hence statement 1 is not correct.
- The Nari Adalat though does not hold any legal status, has its primary focus on reconciliation, grievance redressal and creating awareness of rights and entitlements. Hence statement 2 is correct.
- It will cater to all women and girls who require assistance or have grievances within the local community. Hence statement 3 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations
RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

43. उत्तर B
- उप-योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 (चार) वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

44. उत्तर B
- टेली मानस को दो-स्तरीय प्रणाली के रूप में आयोजित किया जाएगा। टियर 1 में राज्य टेली मानस सेल शामिल होंगे, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं।
- टियर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP)/मेडिकल कॉलेज संसाधनों के विशेषज्ञ और/या ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए ई-संजीवनी शामिल होंगे। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

45. उत्तर B
- यह योजना मिशन शक्ति की संबल उप-योजना के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी, जो महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- नारी अदालत को कोई कानूनी दर्जा नहीं है, लेकिन इसका प्राथमिक ध्यान सुलह, शिकायत निवारण और अधिकारों और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर है। अतः कथन 2 सही है।
- यह उन सभी महिलाओं और लड़कियों की मदद करेगा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है या स्थानीय समुदाय में उनकी शिकायतें हैं। अतः कथन 3 सही है।

46. Answer C
- The Union Cabinet Chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has approved the overarching scheme "PRITHvi VIgyan (PRITHVI)" of the Ministry of Earth Sciences, for implementation during the period from 2021-26 at an overall cost of Rs. 4,797 crore.
- The scheme encompasses five ongoing sub-schemes namely
    - "Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services (ACROSS)"
    - "Ocean Services, Modelling Application, Resources and Technology (O-SMART)"
    - "Polar Science and Cryosphere Research (PACER)"
    - "Seismology and Geosciences (SAGE)"
    - "Research, Education, Training and Outreach (REACHOUT)"

47. Answer B
- The criteria generally adopted for specification of a community as a scheduled tribe are: (a) indications of primitive traits; (b) distinctive culture; (c) shyness of contact with the community at large; and (d) geographical isolation, i.e., backwardness.
- These are not spelt out in the Constitution but have become well established. They take into account the definitions in the 1931 Census, the reports of the first Backward Classes Commission (Kalelkar Committee), 1955, the Advisory Committee on Revision of SC/ST lists (Lokur Committee), 1965 and the Joint Committee of Parliament on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967 (Chanda Committee),1969. Hence statement 2 is not correct.
- The guiding principle is that no person who is not a scheduled tribe by birth will be deemed to be a member of scheduled tribe merely because he or she has married a person belonging to a scheduled tribe. Similarly, a person who is a member of a scheduled tribe will continue to be a member of that scheduled tribe, even after his or her marriage with a person who does not belong to a scheduled tribe. Hence statement 4 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

46. उत्तर C
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-26 की अवधि के दौरान 4,797 करोड़ रुपये की कुल लागत से कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना "पृथ्वी विज्ञान (PRITHVI)" को मंजूरी दे दी है। इस योजना में पांच चालू उप-योजनाएं शामिल हैं, अर्थात्
    - "वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं (एक्रॉस)"
    - "महासागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)"
    - "ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (पेसर)"
    - "भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान (एसएजीई)"
    - "अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच (रीचआउट)"

47. उत्तर B
- किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए आम तौर पर अपनाए जाने वाले मानदंड हैं: (a) आदिम लक्षणों के संकेत; (b) विशिष्ट संस्कृति; (c) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म; और (d) भौगोलिक अलगाव, यानी पिछड़ापन। इन्हें संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है लेकिन ये अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं।
- वे 1931 की जनगणना में दी गई परिभाषाओं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेकर समिति), 1955 की रिपोर्ट, एससी/एसटी सूचियों के संशोधन पर सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 पर संसद की संयुक्त समिति (चंदा समिति), 1969 को ध्यान में रखते हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
- मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया है। इसी तरह, कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा, भले ही उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो अनुसूचित जनजाति का नहीं है। इसलिए कथन 4 सही नहीं है।

48. Answer B
- Survey of India (SOl), the national survey and mapping organisation under the Ministry of Science and Technology, was set up in 1767. Hence statement 1 is not correct.
- Headquartered in Kolkata, National Atlas and Thematic Mapping Organisation (NATMO) is a subordinate office under the Department of Science & Technology, Ministry of Science & Technology, Government of India. Pioneer in thematic mapping services since its inception in 1956, NATMO is the only agency of the country catering to the requirements of thematic maps and atlases for different sectors. NATMO is perhaps the largest mapping organisation in the world. Hence statement 3 is not correct.

49. Answer A
- The National Mission for Manuscripts (NMM) was established in February 2003, by the Ministry of Tourism and Culture, Government of India. It has been made an integral part of the Indira Gandhi National Center for the Arts (IGNCA) and will function as an independent Division of IGNCA. Hence, statement 1 is not correct.
- The Mission seeks to unearth and preserve the vast manuscript wealth of India. These cover a variety of themes, textures and aesthetics, scripts, languages, calligraphies, illuminations, and illustrations. Lithographs and printed volumes are not considered manuscripts. Hence, statement 2 is not correct.

50. Answer C
- Children who have lost both parents or their lone surviving parent or their legal guardian or adoptive parent due to COVID-19 are the beneficiaries. Hence statement 1 is correct.
- The Fund is a public charitable trust with the Prime Minister as its Chairman. Other Members include Defence Minister, Home Minister and, Finance Minister are ex-officio Trustees of the Fund. Hence statement 2 is correct.
- The fund consists entirely of voluntary contributions from individuals/organizations and does not get any budgetary support. Hence statement 3 is correct.

48. उत्तर B
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) की स्थापना 1767 में की गई थी। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- कोलकाता में मुख्यालय वाला, राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन (NATMO) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। 1956 में अपनी स्थापना के बाद से विषयगत मानचित्रण सेवाओं में अग्रणी, NATMO देश की एकमात्र एजेंसी है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए विषयगत मानचित्रों और एटलस की आवश्यकताओं को पूरा करती है। NATMO शायद दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्रण संगठन है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

49. उत्तर A
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) की स्थापना फरवरी 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) का एक अभिन्न अंग बनाया गया है और यह IGNCA के एक स्वतंत्र प्रभाग के रूप में कार्य करेगा। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- मिशन भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा को उजागर करने और संरक्षित करने का प्रयास करता है। इनमें विभिन्न प्रकार के विषय, बनावट और सौंदर्यशास्त्र, लिपियाँ, भाषाएँ, सुलेख, रोशनी और चित्रण शामिल हैं। लिथोग्राफ और मुद्रित संस्करणों को पांडुलिपियाँ नहीं माना जाता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।.

50. उत्तर C
- जिन बच्चों ने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता या अपने एकमात्र जीवित माता-पिता या अपने कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया है, वे लाभार्थी हैं। इसलिए कथन 1 सही है।
- यह फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं, जो फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। इसलिए कथन 2 सही है।
- यह कोष पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों के स्वैच्छिक योगदान से बना है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। अतः कथन 3 सही है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

51. Answer B

- NSGM Project Management Unit (NPMU), headed by the Director NPMU: The NSGM Project Management Unit (NPMU) is the implementing agency for operationalizing the Smart Grid activities in the country under the guidance of the Governing Council and Empowered Committee. Each of the States also has a State Level Project Management Unit (SLPMU), which is chaired by the Power Secretary of the State. Hence statement 3 is not correct.

52. Answer A

- The central government will make wage-related decisions for employment such as railways,mines, and oil fields, among others.
- State governments will make decisions for all other employment.
- Wages include salary, allowance, or any other component expressed in monetary terms. This does not include bonus payable to employees or any travelling allowance. Hence statement 2 is not correct.
- The central government will fix a floor wage, considering living standards of workers. The central government may obtain the advice of the Central Advisory Board and may consult with state governments. Hence statement 3 is not correct.

53. Answer C

- In the seventies, the United Nations Convention on the Laws of the Sea (UNCLOS) awarded Exclusive Economic Zones (EEZ) to all coastal states. Thereafter, the government enacted the Maritime Zones of India Act 1976 and acquired sovereign rights over 2.01 million sqm area as the Exclusive Economic Zone;
- The discovery of oil in Mumbai (then Bombay) High and subsequent development of high-value offshore installations, also necessitated measures of protection and disaster response in this. Hence, both statement 1 and statement 2 are correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

51. उत्तर B

- NSGM परियोजना प्रबंधन इकाई (NPMU), NPMU के निदेशक की अध्यक्षता में: NSGM परियोजना प्रबंधन इकाई (NPMU) शासी परिषद और अधिकार प्राप्त समिति के मार्गदर्शन में देश में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई (SLPMU) भी होती है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के बिजली सचिव करते हैं। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

52. उत्तर A

- केंद्र सरकार रेलवे, खदानों और तेल क्षेत्रों जैसे रोजगार के लिए वेतन संबंधी निर्णय लेगी। राज्य सरकारें अन्य सभी रोजगार के लिए निर्णय लेंगी।
- मजदूरी में वेतन, भत्ता या मौद्रिक शब्दों में व्यक्त कोई अन्य घटक शामिल है। इसमें कर्मचारियों को देय बोनस या कोई यात्रा भत्ता शामिल नहीं है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
- केंद्र सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम वेतन तय करेगी। केंद्र सरकार केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह ले सकती है और राज्य सरकारों से परामर्श कर सकती है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

53. उत्तर C

- सत्तर के दशक में, समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) ने सभी तटीय राज्यों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) प्रदान किए। इसके बाद, सरकार ने भारत के समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 को अधिनियमित किया और विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में 2.01 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार हासिल किए;
- मुंबई (तब बॉम्बे) हाई में तेल की खोज और उसके बाद उच्च-मूल्य वाले अपतटीय प्रतिष्ठानों के विकास ने भी इस क्षेत्र में सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया के उपायों की आवश्यकता पैदा कर दी। इसलिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।

54. Answer C
- Seed capital @ Rs. 40,000/- per SHG member for working capital and purchase of small tools. Hence statement 1 is correct.
- The scheme provides 50% financial grant for Branding and Marketing Support to groups of FPOs/ SHGs/ Cooperatives or a SPV of micro food processing enterprises to promote their existing or proposed brands to market their processed food products under the scheme. Hence statement 2 is correct.

55. Answer C
- The landmark legislation Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA), encourages greater transparency,
- citizen centricity, accountability and financial discipline.
- Only new projects are covered by the Act. Projects that are ongoing, completed or stuck due to clearance or financial issues, don't come under this.Hence option (c) is the correct answer.

56. Answer C

A Quantum Key Distribution (QKD) system is a secure communication method that implements a cryptographic protocol involving the principles of quantum mechanics. It enables two parties to produce a shared random secret key known only to them, which can then be used to encrypt & decrypt messages. Hence statement 1 is correct

.

57. Answer A
- Under the provision of the Act, both the central and state governments are the appropriate governments to fix, revise, review and enforce the payment of minimum wages to workers in respect of scheduled employment under their respective jurisdictions. Hence statement 2 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

54. उत्तर सी
- कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए एसएचजी सदस्य को 40,000 रुपये की बीज पूंजी। इसलिए कथन 1 सही है।
- यह योजना एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन सहायता के लिए 50% वित्तीय अनुदान प्रदान करती है ताकि योजना के तहत अपने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बाजार में लाने के लिए अपने मौजूदा या प्रस्तावित ब्रांडों को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए कथन 2 सही है।

55. उत्तर C
- ऐतिहासिक कानून रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA), अधिक पारदर्शिता, नागरिक केंद्रितता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करता है।
- केवल नई परियोजनाएँ अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। परियोजनाएँ जो चल रही हैं, पूरी हो चुकी हैं या मंजूरी या वित्तीय मुद्दों के कारण अटकी हुई हैं, इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। इसलिए विकल्प (c) सही उत्तर है।

56. उत्तर C

क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) प्रणाली एक सुरक्षित संचार पद्धति है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को शामिल करते हुए एक क्रिप्टोग्राफ़िक प्रोटोकॉल को लागू करती है। यह दो पक्षों को केवल उनके लिए ज्ञात एक साझा यादृच्छिक गुप्त कुंजी बनाने में सक्षम बनाता है, जिसका उपयोग संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए कथन 1 सही है।

57. उत्तर A
- अधिनियम के प्रावधान के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अनुसूचित रोजगार के संबंध में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को तय करने, संशोधित करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

58. Answer A
- The Mid-Day Meal (MDM) Rules were notified under the National Food Security Act, 2013. All the states/UTs have been advised to disseminate and enforce the MDM Rules 2015 in all eligible schools. Hence statement 1 is not correct.
- supply of foodgrains at NFSA rates of ₹3 Per kg for rice and ₹2 per kg for wheat instead of BPLrates of ₹5.65 and ₹4.15 per kg respectively. Hence statement 2 is not correct.

59. Answer C
- The Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO), an attached office of NITI Aayog, is the apex monitoring and evaluation (M&E) office of the Government of India. Hence statement 2 is correct.
- It was established in September 2015 by merging the erstwhile Programme Evaluation Office (PEO) and the Independent Evaluation Office (IEO). Hence statement 1 is correct.

60. Answer D
- 'Sahi Fasal' campaign, an awareness generation campaign, was launched by the National Water MissionMinistry of Jal Shakti in 2019 to nudge the farmers in the water stressed areas to grow less water intensive, economically remunerative and environmentally friendly crops. Hence statement 1 is not correct.
- Since this is an awareness generation campaign, no separate allocation of funds has been made by this Ministry for the 'Sahi Fasal' campaign. Water being a state subject, State Governments use their own resources on the basis of their planning and priorities. Hence statement 2 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

58. उत्तर A
- मध्याह्न भोजन (MDM) नियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित किए गए थे। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र स्कूलों में MDM नियम 2015 का प्रसार और प्रवर्तन करने की सलाह दी गई है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- चावल के लिए ₹3 प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से एनएफएसए दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति क्रमशः बीपीएल दरों ₹5.65 और ₹4.15 प्रति किलोग्राम के बजाय। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

59. उत्तर C
- विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO), नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय, भारत सरकार का सर्वोच्च निगरानी और मूल्यांकन (M&E) कार्यालय है। इसलिए कथन 2 सही है।
- इसे सितंबर 2015 में पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय (PEO) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) को मिलाकर स्थापित किया गया था। इसलिए कथन 1 सही है।

60ण उत्तर D
• 'सही फ़सल' अभियान, एक जागरूकता सृजन अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को कम पानी की गहन, आर्थिक रूप से पारिश्रमिक और पर्यावरण के अनुकूल फ़सलें उगाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

• चूंकि यह एक जागरूकता सृजन अभियान है, इसलिए इस मंत्रालय द्वारा 'सही फ़सल' अभियान के लिए धन का कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है जल राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपनी योजना और प्राथमिकताओं के आधार पर अपने संसाधनों का उपयोग करती हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

61. Answer B

Department of Administrative Reforms and Public Grievances, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, in its efforts to provide more responsive and citizen-friendly governance, coordinates the efforts to formulate and operationalize Citizens Charters. Various Central Government Ministries/ Departments/ Organisations have brought out their Citizens' Charters. With a view to ensure effective implementation of the Citizens' Charter, Nodal Officers have been appointed in the concerned Central Government Ministries/Departments/ Organisations. Hence, statement 2 is not correct.

62. Answer D

- Nivaran is an online grievance redressal system launched by the Ministry of Railways. Hence statement 1 is not correct.
- It is designed to facilitate railway employees and pensioners to lodge their grievances and monitor their progress. Hence statement 2 is not correct.

63. Answer C

- The Cargo handling capacity at the airport was at 7.4 million metric tonnes in FY22, 7.5MMT in FY23 and 8 MMT in FY24. Therefore, the cargo handling capacity has steadily increased since FY22.
- As of the FY24, the top Indian airports by cargo handling capacity are:
- Indira Gandhi International Airport: 1MMT. Hence, option (c) is the correct answer

64. Answer D

- India's school education system serves 24.8 crore students across 14.72 lakh schools with 98 lakh teachers (UDISE+ 2023-24). Government schools make up 69 per cent of the total, enrolling 50 per cent of students and employing 51 per cent of teachers, while private schools account for 22.5 per cent, enrolling 32.6 percent of students and employing 38 percent of teachers. The National EDucation Policy, 2020 aims for a 100 percent Gross Enrolment Ratio (GER) by 2030. The GER is near-universal at the primary (93 per cent) and the efforts are underway to bridge the gaps at the secondary (77.4 percent) and higher secondary level (56.2 per cent), driving the nation closer to its vision of inclusive and equitable education for all. Hence option (d) is the correct answer.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

61. उत्तर B

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, अधिक उत्तरदायी और नागरिक-अनुकूल शासन प्रदान करने के अपने प्रयासों में, नागरिक चार्टर तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के प्रयासों का समन्वय करता है। विभिन्न केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने अपने नागरिक चार्टर जारी किए हैं। नागरिक चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

62. उत्तर D

• निवारण रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

• इसे रेलवे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने की सुविधा के लिए बनाया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

63. उत्तर C

- हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता वित्त वर्ष 22 में 7.4 मिलियन मीट्रिक टन, वित्त वर्ष 23 में 7.5MMT और वित्त वर्ष 24 में 8 MMT थी। इसलिए, वित्त वर्ष 22 से कार्गो हैंडलिंग क्षमता में लगातार वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 24 तक, कार्गो हैंडलिंग क्षमता के हिसाब से शीर्ष भारतीय हवाई अड्डे हैं:
- इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: 1MMT। इसलिए, विकल्प (c) सही उत्तर है

64. उत्तर D

- भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 14.72 लाख स्कूलों में 98 लाख शिक्षकों (UDISE+ 2023-24) के साथ 24.8 करोड़ छात्रों को सेवा प्रदान करती है। सरकारी स्कूल कुल का 69 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, 50 प्रतिशत छात्रों का नामांकन करते हैं और 51 प्रतिशत शिक्षकों को रोजगार देते हैं, जबकि निजी स्कूलों में 22.5 प्रतिशत हिस्सा है, 32.6 प्रतिशत छात्रों का नामांकन करते हैं और 38 प्रतिशत शिक्षकों को रोजगार देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लक्ष्य 2030 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER) है। प्राथमिक (93 प्रतिशत) में जीईआर लगभग सार्वभौमिक है और माध्यमिक (77.4 प्रतिशत) और उच्चतर माध्यमिक स्तर (56.2 प्रतिशत) पर अंतराल को पाटने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे राष्ट्र सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा के अपने दृष्टिकोण के करीब पहुंच रहा है। इसलिए विकल्प (d) सही उत्तर है।

65. Answer B

Centrally Sponsored Scheme 'Support to State Extension Programs for Extension Reforms," popularly known as ATMA Scheme, has been under implementation since 2005. The scheme promotes a decentralized farmer-friendly extension system in the country. The objectives of the Scheme are to support the State Government's efforts and to make available the latest agricultural technologies and good agricultural practices in different thematic areas of agriculture and allied areas to farmers through different extension activities viz; Farmers Training, Demonstrations, Exposure Visits, Kisan Mela, Mobilization of Farmers Groups and organizing Farm Schools, etc. Hence statement 1 is not correct.

66. Answer A

- The Union Budget 2025-26 has set a target to reduce the fiscal deficit to 4.5% of GDP by 2026-27 as part of the government's fiscal consolidation roadmap. Hence, statement-I is correct.
- The FRBM's 3% fiscal deficit target is a long-term fiscal policy goal. Hence, statement-II is correct.

67. Answer C

- Over the past two years, India's food inflation rate has remained firm, diverging from global
- trends of stable or declining food inflation. Hence statement 2 is correct.
- Vegetables and pulses together hold a total weightage of 8.42 per cent in CPI basket. However, their contribution to the overall inflation stood at 32.3 percent in FY25 (April to December).
- When Vegetables and pulses are excluded, the average food inflation rate for FY25 (April December) was 4.3 per cent, which is 4.1 percent lower than the overall food inflation.
- Similarly, the average headline inflation would be 3.2 percent when the vegetables and pulses inflation rates were excluded, 1.7 percent lower than the actual headline inflation.
- Thus, Vegetables and Pulses drove food inflation in India in the last two years. Hence statement 1 is correct.

65. उत्तर B

केंद्र प्रायोजित योजना 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन', जिसे ATMA योजना के रूप में जाना जाता है, 2005 से कार्यान्वयन में है। यह योजना देश में विकेन्द्रीकृत किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। योजना का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करना और विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीकों और अच्छी कृषि प्रथाओं को उपलब्ध कराना है; किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला, किसान समूहों का जुटान और फार्म स्कूल का आयोजन, आदि। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

66. उत्तर A

- केंद्रीय बजट 2025-26 ने सरकार के राजकोषीय समेकन रोडमैप के हिस्से के रूप में 2026-27 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए, कथन-I सही है।
- FRBM का 3% राजकोषीय घाटा लक्ष्य एक दीर्घकालिक राजकोषीय नीति लक्ष्य है। इसलिए, कथन-II सही है।

67. उत्तर C

- पिछले दो वर्षों में, भारत की खाद्य मुद्रास्फीति दर स्थिर या घटती खाद्य मुद्रास्फीति के वैश्विक रुझानों से अलग होकर स्थिर बनी हुई है। इसलिए कथन 2 सही है।
- सब्जियों और दालों का कुल मिलाकर सीपीआई बास्केट में 8.42 प्रतिशत का भार है। हालांकि, वित्त वर्ष 25 (अप्रैल से दिसंबर) में समग्र मुद्रास्फीति में उनका योगदान 32.3 प्रतिशत रहा।
- जब सब्ज़ियों और दालों को बाहर रखा जाता है, तो वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) के लिए औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर 4.3 प्रतिशत थी, जो समग्र खाद्य मुद्रास्फीति से 4.1 प्रतिशत कम है।
- इसी तरह, जब सब्ज़ियों और दालों की मुद्रास्फीति दरों को बाहर रखा जाता है, तो औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत होगी, जो वास्तविक हेडलाइन मुद्रास्फीति से 1.7 प्रतिशत कम है। इस प्रकार, पिछले दो वर्षों में भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को सब्ज़ियों और दालों ने बढ़ाया है। इसलिए कथन 1 सही है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

68. Answer C

- The Annual Survey of Industries (ASI) results for the FY23 highlight indicate a continued increase in the number of large factories i.e., those employing more than 100 workers. The number of such factories saw a robust growth of 7 per cent compared to FY22, while small factories (employing fewer than 100 workers) also experienced a steady increase of 2 per cent. Notably, large factories now account for around 22 per cent of all operational factories, reflecting their growing presence and contribution to the industrial landscape. Hence, statement 1 is correct.
- In terms of the share of employment, large factories continue to employ about 80 percent of the total workers and 78 per cent of the TPE in the sector, whereas small factories, although larger in number, comprise a smaller share of employment in the sector. Hence, statement 2 is correct

69. Answer C

The Union Budget 2025-26 has set a target of 100 GW nuclear power capacity by 2047, and Small Modular Reactors (SMRs) are expected to contribute significantly to this goal.

70. Answer D

Among the other cleaner sources of energy, nuclear, being an efficient source of energy, has increasingly emerged as a reliable alternative to fossil fuel. However, there are challenges. The expansion of the use of nuclear power has to contend with public concerns about safety and the uncertainty that the latest technologies are controlled by a few countries. The Geographical concentration (Economic Survey, 2022-2023; 2023-2024) of uranium and other essential minerals also poses a challenge. Besides, nuclear energy relies heavily on the stability of fossil fuel supply chains to produce sulfuric acid for uranium extraction. Hence option (d) is the correct answer.

68. उत्तर C

- वित्त वर्ष 23 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के परिणाम बड़े कारखानों की संख्या में निरंतर वृद्धि को इंगित करते हैं, यानी, 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले। ऐसे कारखानों की संख्या में वित्त वर्ष 22 की तुलना में 7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई, जबकि छोटे कारखानों (100 से कम श्रमिकों को रोजगार देने वाले) में भी 2 प्रतिशत की लगातार वृद्धि हुई। उल्लेखनीय रूप से, बड़े कारखाने अब सभी चालू कारखानों का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो औद्योगिक परिदृश्य में उनकी बढ़ती उपस्थिति और योगदान को दर्शाता है। इसलिए, कथन 1 सही है।
- रोजगार के हिस्से के संदर्भ में, बड़े कारखाने कुल श्रमिकों के लगभग 80 प्रतिशत और क्षेत्र में टीपीई के 78 प्रतिशत को रोजगार देना जारी रखते हैं, जबकि छोटे कारखाने, हालांकि संख्या में बड़े हैं, इस क्षेत्र में रोजगार का एक छोटा हिस्सा बनाते हैं। इसलिए, कथन 2 सही है

69. उत्तर C

केंद्रीय बजट 2025-26 में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) से इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

70. उत्तर D

ऊर्जा के अन्य स्वच्छ स्रोतों में, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा का एक कुशल स्रोत होने के नाते, जीवाश्म ईंधन के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में तेजी से उभरा है। हालाँकि, चुनौतियाँ हैं। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विस्तार को सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक चिंताओं और इस अनिश्चितता से जूझना पड़ता है कि नवीनतम तकनीकों को कुछ देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यूरेनियम और अन्य आवश्यक खनिजों की भौगोलिक सांद्रता (आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-2023; 2023-2024) भी एक चुनौती है। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा यूरेनियम निष्कर्षण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने के लिए जीवाश्म ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इसलिए विकल्प (d) सही उत्तर है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

71. Answer A

Several studies have also assessed the overall effect of climate change on agricultural production. Negi and Ramaswami (2024) 21 examined the relationship between crop yields and rainfall across India at the district level for nine key crops during the kharif season. They found a strong link between significant rainfall shortfalls and substantial crop yield losses. This statistical phenomenon is known as lower tail dependence, indicating that the correlation between yield losses and rainfall is stronger for extreme rainfall deficiencies than for minor variations

72. Answer D

- The Production Linked Incentive Scheme for Food Processing (PLISFPI), launched in 2021, seeks to cultivate globally competitive food processing leaders by facilitating branding and marketing initiatives in international markets. By 31 October 2024, 171 applications had been approved under this scheme, with beneficiaries investing ₹8,910 crore and receiving ₹1,084.01 crore in incentives. Hence statement 3 is not correct.
- To improve food grain storage, especially in hilly and remote areas, the government is exploring using Flospan, a type of mobile storage unit (MSU), in collaboration with the World Food Programme (WFP). These units can be quickly erected and have a storage capacity of 400 metric tonnes. As a pilot project, WFP has installed Flospan in six states. Hence statement 1 is not correct.
- Notably, the share of processed food exports within agrifood exports has risen from 14.9 percent in FY18 to 23.4 percent in FY24. Hence statement 2 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

71. उत्तर A

कई अध्ययनों ने कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के समग्र प्रभाव का भी आकलन किया है। नेगी और रामास्वामी (2024) 21 ने खरीफ मौसम के दौरान नौ प्रमुख फसलों के लिए जिला स्तर पर भारत भर में फसल की पैदावार और वर्षा के बीच संबंधों की जांच की। उन्होंने महत्वपूर्ण वर्षा की कमी और पर्याप्त फसल उपज के नुकसान के बीच एक मजबूत संबंध पाया। इस सांख्यिकीय घटना को लोअर टेल डिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है, जो दर्शाता है कि उपज के नुकसान और वर्षा के बीच संबंध मामूली बदलावों की तुलना में अत्यधिक वर्षा की कमी के लिए अधिक मजबूत है।

72. उत्तर D

- खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISFPI), 2021 में शुरू की गई, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्रांडिंग और विपणन पहलों को सुविधाजनक बनाकर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खाद्य प्रसंस्करण नेताओं को विकसित करना चाहती है। 31 अक्टूबर 2024 तक, इस योजना के तहत 171 आवेदनों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें लाभार्थियों ने ₹8,910 करोड़ का निवेश किया और प्रोत्साहन में ₹1,084.01 करोड़ प्राप्त किए। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।
- खाद्यान्न भंडारण में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में, सरकार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के सहयोग से फ्लोस्पैन, एक प्रकार की मोबाइल भंडारण इकाई (एमएसयू) का उपयोग करने की संभावना तलाश रही है। इन इकाइयों को जल्दी से स्थापित किया जा सकता है और इनकी भंडारण क्षमता 400 मीट्रिक टन है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, डब्ल्यूएफपी ने छह राज्यों में फ्लोस्पैन स्थापित किया है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- विशेष रूप से, कृषि खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 18 में 14.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 23.4 प्रतिशत हो गई है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

73. Answer D

- India is the seventh most vulnerable country to climate change. It suffers from weather extremes and hazards, slow onset events such as sea-level rise, biodiversity loss, and water insecurity.
- Indians's ambition to achieve developed nation status by 2047 is fundamentally anchored in the vision of inclusive and sustainable development. Notably, India's per capita carbon emissions are one-third of the global average.
- A strong adaptation strategy is a priority for the country, given its significant vulnerability to climate change, stemming from its geographic and agro-climatic diversity. India's Initial Adaptation Communication, submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in December 2023, reveals that the total expenditure related to adaptation in FY22 was 5.6 per cent of the Gross Domestic Product (GDP), an increase from 3.7 per cent in FY16. Climate action, so far, has been financed through domestic resources, with the public sector playing a central role. On the other hand, the international flow of funds for climate actions is highly inadequate and has a mitigation bias. Hence statements 3 and 4 are correct.

74. Answer C

- During the five years from FY21 (pandemic year) to FY25 (BE), the SSE grew at a CAGR of 15 per cent. While the SSE outlay of the centre and state governments was ₹14.8 lakh crore in FY21, it has increased steadily to stand at ₹25.7 lakh crore in FY25 (BE). Hence statement 1 is correct.
- Expenditure on education has grown at a CAGR of 12 per cent from ₹ 5.8 lakh crore in FY21 to ₹ 9.2 lakh crore in FY25 (BE). Expenditure on

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

73. उत्तर D

- भारत जलवायु परिवर्तन के लिए सातवाँ सबसे संवेदनशील देश है। यह मौसम की चरम स्थितियों और खतरों, समुद्र के स्तर में वृद्धि, जैव विविधता की हानि और जल असुरक्षा जैसी धीमी शुरुआत वाली घटनाओं से ग्रस्त है।
- 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने की भारतीयों की महत्वाकांक्षा मूल रूप से समावेशी और सतत विकास की दृष्टि पर आधारित है। उल्लेखनीय बात यह है कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का एक तिहाई है।
- देश के लिए एक मजबूत अनुकूलन रणनीति एक प्राथमिकता है, क्योंकि इसकी भौगोलिक और कृषि-जलवायु विविधता से उपजी जलवायु परिवर्तन के प्रति इसकी महत्वपूर्ण भेद्यता है। दिसंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत भारत के प्रारंभिक अनुकूलन संचार से पता चलता है कि वित्त वर्ष 22 में अनुकूलन से संबंधित कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.6 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 16 में 3.7 प्रतिशत से अधिक है। जलवायु कार्रवाई, अब तक, घरेलू संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित की गई है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। दूसरी ओर, जलवायु क्रियाओं के लिए धन का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह अत्यधिक अपर्याप्त है और इसमें शमन पूर्वाग्रह है। इसलिए कथन 3 और 4 सही हैं

74. उत्तर C

- वित्त वर्ष 21 (महामारी वर्ष) से वित्त वर्ष 25 (बीई) तक के पाँच वर्षों के दौरान, एसएसई 15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। जबकि केंद्र और राज्य सरकारों का एसएसई परिव्यय वित्त वर्ष 21 में ₹14.8 लाख करोड़ था, यह लगातार बढ़कर वित्त वर्ष 25 (बीई) में ₹25.7 लाख करोड़ हो गया है। अतः कथन 1 सही है।
- शिक्षा पर व्यय 12 प्रतिशत की CAGR से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में ₹ 5.8 लाख करोड़ से वित्त वर्ष 25 (बीई) में ₹ 9.2 लाख करोड़ हो गया है। स्वास्थ्य पर व्यय 18 प्रतिशत की CAGR से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में ₹ 3.2 लाख करोड़ से वित्त वर्ष 25 (बीई) में ₹ 6.1 लाख करोड़ हो गया। अतः कथन 2 सही है।

75. Answer B

The government has announced unlimited procurement of Tur, Urad, and Masoor pulses for four years through National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) and National Cooperative Consumers' Federation of India Limited (NCCF) benefiting registered farmers. Hence, statement 3 is not correct.

76. Answer A

- For 23 States, GST was the main source of revenue amongst own revenue receipts (ORR) with the greatest reliance thereon by Manipur and Nagaland at 78 percent and 72 percent, respectively. Hence statement 1 is not correct.
- States garnering the highest shares in respective ORRs w.r.t. stamps & registration, sales tax and state excise duties were Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal, respectively. Hence statement 3 is correct.
- Odisha exhibited the highest share of non-tax revenue in ORR at 49 percent. Hence statement 2 is not correct

77. Answer A

- In a significant move to support the agricultural sector and address rising input costs, the Reserve Bank of India has announced an increase in the limit for collateral-free agricultural loans, including loans for allied activities.
- The existing loan limit of ₹1.6 lakh per borrower has been raised to ₹2 lakh

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

75ण उत्तर B

सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) के माध्यम से पंजीकृत किसानों को लाभान्वित करते हुए चार वर्षों के लिए तुअर, उड़द और मसूर दालों की असीमित खरीद की घोषणा की है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

76. उत्तर A

- 23 राज्यों के लिए, जीएसटी उनकी स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (ओआरआर) में राजस्व का मुख्य स्रोत था, जिस पर मणिपुर और नागालैंड क्रमशः 78 प्रतिशत और 72 प्रतिशत पर सबसे अधिक निर्भरता रखते थे स्टाम्प एवं पंजीकरण, बिक्री कर और राज्य उत्पाद शुल्क क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल थे। इसलिए कथन 3 सही है।
- ओडिशा ने ओआरआर में गैर-कर राजस्व का सबसे अधिक हिस्सा 49 प्रतिशत प्रदर्शित किया। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

77ण उत्तर A

- कृषि क्षेत्र का समर्थन करने और बढ़ती इनपुट लागतों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा में वृद्धि की घोषणा की है।
- प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख की मौजूदा ऋण सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

78. Answer C

- The livestock sector has emerged as a significant engine of growth in agriculture, playing a vital role in the overall agricultural landscape. The economic significance of this sector is clearly illustrated by its escalating output value, which reached an astounding 17.25 lakh crore rupees (equivalent to US$205.81 billion) in FY23. Among the various branches of livestock production, the milk industry generated the highest revenue, surpassing even paddy and wheat production, generating over ₹11.16 lakh crore (US$133.16 billion) in revenue. Hence statement 1 is correct.
- The government has supported the livestock sector through various initiatives by recognizing the growing importance of the livestock sector and its potential to boost farm incomes. The mechanism of Multipurpose AI Technicians in Rural India (MAITRIs) has been established to deliver breeding inputs to farmers' at their doorstep. Under the scheme, MAITRIs are trained and equipped to deliver quality artificial insemination services to farmers' doorsteps. During the last 3 years, 38,736 MAITRIs have been trained and equipped under Rashtriya Gokul Mission. Hence statement 2 is correct.

79. Answer: C.

Moderate deficit with robust services trade offsetting goods trade imbalance

Explanation:

The services sector, especially IT exports, helped cushion the trade deficit, leading to a manageable current account deficit around 1.5–2% of GDP.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations
RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

78. उत्तर C

- पशुधन क्षेत्र कृषि में विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में उभरा है, जो समग्र कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व इसके बढ़ते उत्पादन मूल्य से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जो वित्त वर्ष 23 में आश्चर्यजनक 17.25 लाख करोड़ रुपये (US$205.81 बिलियन के बराबर) तक पहुँच गया। पशुधन उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में, दूध उद्योग ने सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न किया, जो धान और गेहूँ उत्पादन से भी आगे निकल गया, जिससे ₹11.16 लाख करोड़ (US$133.16 बिलियन) से अधिक राजस्व उत्पन्न हुआ। इसलिए कथन 1 सही है।
- सरकार ने पशुधन क्षेत्र के बढ़ते महत्व और कृषि आय को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता को पहचानते हुए विभिन्न पहलों के माध्यम से पशुधन क्षेत्र का समर्थन किया है। किसानों को उनके दरवाजे पर प्रजनन इनपुट देने के लिए ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियन (MAITRI) की व्यवस्था स्थापित की गई है। इस योजना के तहत, MAITRI को किसानों के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ देने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 38,736 MAITRI को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है। इसलिए कथन 2 सही है।

79. उत्तर: C.

मजबूत सेवा व्यापार के साथ मध्यम घाटा माल व्यापार असंतुलन की भरपाई करता है

स्पष्टीकरण:

सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी निर्यात ने व्यापार घाटे को कम करने में मदद की, जिससे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5-2% चालू खाता घाटा प्रबंधनीय हो गया।

80. Answer: D.
Explanation:
Statement 1 is correct: "Viksit Bharat @2047" is a government vision to transform India into a fully developed nation by its 100th year of independence. The vision includes structural reforms in economy, digital governance, education, and climate resilience.
Statement 2 is correct: According to the India Year Book 2025, NITI Aayog is coordinating the initiative by engaging states, union territories, and district administrations to build a bottom-up planning framework.
Statement 3 is correct: One of the health pillars includes universal health access, and the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) is integral to this by ensuring a nationwide digital health ecosystem.

81. Answer: C.
India has the world's second-largest elderly population after China
Explanation:
India Year Book 2025 cites UN projections, placing India as the second-largest elderly population in absolute numbers, after China. However, India's working-age population is still growing, and the median age is slightly under 30. Dependency ratio remains lower than in 2011 due to a younger population.

82. Answer:B.
Financial sector reforms (the horse) must precede credit expansion (the cart) to ensure sustainable lending.
Explanation:
The Economic Survey 2024–25 uses the metaphor of "the cart and the horse" to emphasize that a strong and stable financial sector (the horse) must lead credit growth (the cart). Merely pushing liquidity or encouraging credit expansion without prior reforms in asset quality, banking regulation, and NBFC health would be putting the cart before the horse, leading to unsustainable outcomes.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

80. उत्तर: D.
स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: "विकसित भारत @2047" भारत को स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र में बदलने का एक सरकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में अर्थव्यवस्था, डिजिटल शासन, शिक्षा और जलवायु लचीलापन में संरचनात्मक सुधार शामिल हैं। कथन 2 सही है: इंडिया ईयर बुक 2025 के अनुसार, नीति आयोग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासनों को शामिल करके एक बॉटम-अप प्लानिंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए पहल का समन्वय कर रहा है। कथन 3 सही है: स्वास्थ्य स्तंभों में से एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच शामिल है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करके इसका अभिन्न अंग है।

81. उत्तर: C.
भारत में चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुजुर्ग आबादी है

स्पष्टीकरण:

भारत वर्ष पुस्तक 2025 संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों का हवाला देती है, जिसमें भारत को चीन के बाद पूर्ण संख्या में दूसरी सबसे बड़ी बुजुर्ग आबादी के रूप में रखा गया है। हालाँकि, भारत की कामकाजी आयु की आबादी अभी भी बढ़ रही है, और औसत आयु 30 से थोड़ी कम है। युवा आबादी के कारण निर्भरता अनुपात 2011 की तुलना में कम है।

82. उत्तर: B.
वित्तीय क्षेत्र के सुधारों (घोड़े) को स्थायी उधार सुनिश्चित करने के लिए ऋण विस्तार (गाड़ी) से पहले होना चाहिए।
व्याख्या:

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 "गाड़ी और घोड़े" के रूपक का उपयोग इस बात पर जोर देने के लिए करता है कि एक मजबूत और स्थिर वित्तीय क्षेत्र (घोड़ा) को ऋण वृद्धि (गाड़ी) का नेतृत्व करना चाहिए। परिसंपत्ति गुणवत्ता, बैंकिंग विनियमन और एनबीएफसी स्वास्थ्य में पूर्व सुधार किए बिना केवल तरलता बढ़ाना या ऋण विस्तार को प्रोत्साहित करना घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा होगा, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर परिणाम सामने आएंगे।

83. Answer: C
Explanation:

Statement 1: Correct – The Survey emphasizes that sub-national reforms and reducing compliance burden across states are key to attracting long-term FDI.

Statement 2: Correct – FDI is being increasingly directed toward high-value sectors such as semiconductors, EVs, and renewables.

Statement 3: Incorrect – India continues to favor liberalizing the automatic route to attract FDI efficiently, not reducing it.

Statement 4: Correct – Reinvested earnings by existing foreign firms signal investor confidence and long-term commitment, which the Survey highlights positively.

84. Answer:C
Explanation:

Statement 1: Correct – The government's capital expenditure push, particularly in infrastructure, is a major pillar for medium-term growth.

Statement 2: Correct – The Survey stresses that deregulation, decriminalization of business laws,

and simplification of compliance norms enhance productivity and investor confidence.

Statement 3: Incorrect – Rising global commodity prices could adversely affect inflation and current account deficit; they are a headwind, not a growth driver.
Statement 4: Correct – Formalization, driven by GST, digital payments, and improved tax administration, has widened the tax base and improved economic resilience.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

83. उत्तर: C
स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही - सर्वेक्षण इस बात पर जोर देता है कि उप-राष्ट्रीय सुधार और राज्यों में अनुपालन बोझ को कम करना दीर्घकालिक FDI को आकर्षित करने की कुंजी है।

कथन 2: सही - FDI को सेमीकंडक्टर, EV और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों की ओर तेजी से निर्देशित किया जा रहा है।

कथन 3: गलत – भारत एफडीआई को कुशलतापूर्वक आकर्षित करने के लिए स्वचालित मार्ग को उदार बनाने का पक्षधर है, न कि इसे कम करने का।

कथन 4: सही – मौजूदा विदेशी फर्मों द्वारा पुनर्निवेशित आय निवेशकों के विश्वास और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का संकेत देती है, जिसे सर्वेक्षण सकारात्मक रूप से उजागर करता है।

84ए उत्तर:C
स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही - सरकार का पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में, मध्यम अवधि की वृद्धि के लिए एक प्रमुख स्तंभ है।

कथन 2: सही - सर्वेक्षण इस बात पर जोर देता है कि विनियमन, व्यावसायिक कानूनों का गैर-अपराधीकरण और अनुपालन मानदंडों का सरलीकरण उत्पादकता और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है।

कथन 3: गलत - वैश्विक कमोडिटी की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं; वे विकास को गति देने वाले नहीं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं।

कथन 4: सही - जीएसटी, डिजिटल भुगतान और बेहतर कर प्रशासन द्वारा संचालित औपचारिकता ने कर आधार को व्यापक बनाया है और आर्थिक लचीलेपन में सुधार किया है।

85. Answer:A. 1, 2 and 4 only
Explanation:

Statement 1: Correct – The unified portal for business registration streamlines and reduces the time required to start a business.

Statement 2: Correct – The GST reforms aim to simplify compliance and ensure transparent, seamless tax filing, reducing the regulatory burden on businesses.

Statement 3: Incorrect – While SEZs have been a historical part of industrial policy, they have not been directly linked to the recent reforms in the Ease of Doing Business.

Statement 4: Correct – State-level reforms are critical to addressing local regulatory bottlenecks and improving the investment climate across India.

86. Answer: A. 1, 2 and 3 only
Explanation:

Statement 1: Correct – The PLI scheme has been expanded to include sectors like automobiles, textiles, and drones to incentivize domestic production and attract global supply chains.

Statement 2: Correct – FDI in defense is encouraged to modernize the sector and foster technology transfer in line with national security and industrial growth.

Statement 3: Correct – The labor code reforms aim to provide flexible working conditions, promote hire-and-fire policies, and enhance industrial efficiency.

Statement 4: Incorrect – The Survey focuses on promoting IPR protection and enforcement rather than relaxing it, as it is crucial for encouraging innovation and R&D.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

85. उत्तर:A. केवल 1, 2 और 4
स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही - व्यवसाय पंजीकरण के लिए एकीकृत पोर्टल व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक समय को सुव्यवस्थित और कम करता है।

कथन 2: सही – जीएसटी सुधारों का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और पारदर्शी, निर्बाध कर दाखिल करना सुनिश्चित करना है, जिससे व्यवसायों पर विनियामक बोझ कम हो।

कथन 3: गलत – जबकि एसईजेड औद्योगिक नीति का एक ऐतिहासिक हिस्सा रहे हैं, वे हाल ही में व्यापार करने में आसानी के सुधारों से सीधे जुड़े नहीं हैं।

कथन 4: सही – स्थानीय विनियामक बाधाओं को दूर करने और पूरे भारत में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए राज्य-स्तरीय सुधार महत्वपूर्ण हैं।

86. उत्तर:A. केवल 1, 2 और 3
स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही - घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल, कपड़ा और ड्रोन जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पीएलआई योजना का विस्तार किया गया है।

कथन 2: सही - रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा औद्योगिक विकास के अनुरूप प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जा सके। कथन 3: सही - श्रम संहिता सुधारों का उद्देश्य लचीली कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करना, काम पर रखने और निकालने की नीतियों को बढ़ावा देना तथा औद्योगिक दक्षता को बढ़ाना है।

कथन 4: गलत - सर्वेक्षण में आईपीआर संरक्षण और प्रवर्तन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, न कि इसे शिथिल करने पर, क्योंकि यह नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

87. Answer: C
Explanation:

Statement 1: Correct – The Public Distribution System (PDS) has been enhanced using technology, including digital platforms to improve transparency, efficiency, and targeting of benefits.

Statement 2: Correct – The Food Corporation of India (FCI) is being strengthened with additional storage capacity and improved logistics to handle food grain distribution more effectively.

Statement 3: Incorrect – The Survey does not advocate for replacing the PDS system with direct cash transfers but rather aims to improve the current system.

Statement 4: Correct – The integration of agri-tech is emphasized for improving food supply chain efficiency and reducing post-harvest wastage.

88. Answer:C
Statement 1: Correct – The Survey emphasizes the promotion of organic farming and sustainable practices as they can improve soil health and long-term productivity.

Statement 2: Correct – Investment in irrigation infrastructure is a key step to reduce dependence

on monsoons, ensuring stable water supply for agriculture throughout the year.

Statement 3: Correct – Strengthening Farmer Producer Organizations (FPOs) is important for increasing farmers' bargaining power, improving market access, and enhancing economies of scale.

Statement 4: Incorrect – The Survey emphasizes balancing domestic food security while promoting agriculture exports, not prioritizing exports at the cost of domestic needs.

87. उत्तर: C
स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही - पारदर्शिता, दक्षता और लाभों के लक्ष्यीकरण में सुधार के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को बढ़ाया गया है।

कथन 2: सही – भारतीय खाद्य निगम (FCI) को अतिरिक्त भंडारण क्षमता और बेहतर रसद के साथ मजबूत किया जा रहा है ताकि खाद्यान्न वितरण को अधिक प्रभावी ढंग से संभाला जा सके।

कथन 3: गलत – सर्वेक्षण पीडीएस प्रणाली को सीधे नकद हस्तांतरण के साथ बदलने की वकालत नहीं करता है, बल्कि इसका उद्देश्य मौजूदा प्रणाली में सुधार करना है।

कथन 4: सही – खाद्य आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार और कटाई के बाद की बर्बादी को कम करने के लिए कृषि-तकनीक के एकीकरण पर जोर दिया गया है।

88ण उत्तर:C
कथन 1: सही - सर्वेक्षण जैविक खेती और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देता है क्योंकि वे मिट्टी के स्वास्थ्य और दीर्घकालिक उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं।

कथन 2: सही - सिंचाई के बुनियादी ढांचे में निवेश मानसून पर निर्भरता को कम करने, पूरे वर्ष कृषि के लिए स्थिर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

कथन 3: सही - किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करना किसानों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, बाजार तक पहुंच में सुधार करने और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

कथन 4: गलत - सर्वेक्षण घरेलू खाद्य सुरक्षा को संतुलित करने पर जोर देता है जबकि कृषि निर्यात को बढ़ावा देता है, न कि घरेलू जरूरतों की कीमत पर निर्यात को प्राथमिकता देता है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

89. Answer D
- 'Sahi Fasal' campaign, an awareness generation campaign, was launched by the National Water MissionMinistry of Jal Shakti in 2019 to nudge the farmers in the water stressed areas to grow less water intensive, economically remunerative and environmentally friendly crops. Hence statement 1 is not correct.
- Since this is an awareness generation campaign, no separate allocation of funds has been made by this Ministry for the 'Sahi Fasal' campaign. Water being a state subject, State Governments use their own resources on the basis of their planning and priorities. Hence statement 2 is not correct.

90. Answer B

Department of Administrative Reforms and Public Grievances, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, in its efforts to provide more responsive and citizen-friendly governance, coordinates the efforts to formulate and operationalize Citizens Charters. Various Central Government Ministries/ Departments/ Organisations have brought out their Citizens' Charters. With a view to ensure effective implementation of the Citizens' Charter,Nodal Officers have been appointed in the concerned Central Government Ministries/Departments/ Organisations. Hence, statement 2 is not correct.

91. Answer D
- Nivaran is an online grievance redressal system launched by the Ministry of Railways. Hence statement 1 is not correct.
- It is designed to facilitate railway employees and pensioners to lodge their grievances and monitor their progress. Hence statement 2 is not correct.

92. Answer A
- The average container turnaround time in major ports has reduced from 48.1 hours in FY24 to 30.4 hours in FY25. Hence, statement 1 is not correct.
- The GOI has approved the development of the Vadhavan Mega Port with over Rs 76000 crore investment. It is located in Maharashtra (not in Gujarat). Hence, statement 2 is not correct

89. उत्तर D
- 'सही फ़सल' अभियान, एक जागरूकता सृजन अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को कम पानी गहन, आर्थिक रूप से पारिश्रमिक और पर्यावरण के अनुकूल फसलें उगाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- जल राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपनी योजना और प्राथमिकताओं के आधार पर अपने संसाधनों का उपयोग करती हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

90. उत्तर B

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, अधिक उत्तरदायी और नागरिक-अनुकूल शासन प्रदान करने के अपने प्रयासों में, नागरिक चार्टर तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के प्रयासों का समन्वय करता है। विभिन्न केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने अपने नागरिक चार्टर निकाले हैं। नागरिक चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

91. उत्तर D
- निवारण रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
- इसे रेलवे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उनकी प्रगति की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

92. उत्तर A
- प्रमुख बंदरगाहों में औसत कंटेनर टर्नअराउंड समय वित्त वर्ष 24 में 48.1 घंटे से घटकर वित्त वर्ष 25 में 30.4 घंटे हो गया है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- भारत सरकार ने 76000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ वधावन मेगा पोर्ट के विकास को मंजूरी दी है। यह महाराष्ट्र में स्थित है (गुजरात में नहीं)। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

93. Answer C
- The export of services grew at a trend rate of 11 per cent during FY14 to FY23, at constant prices. Hence, statement 1 is correct.
- India remained amongst the top five major countries in terms of growth in services exports in FY25 (April-September). Computer services and business services exports account for around 70 per cent of India's services exports. Hence, statement 2 is correct.

94. Answer A
- The board primarily focuses on domestic processing, value addition, and marketing, not just exports. It aims to strengthen the Makhana supply chain within India and improve farmer earnings rather than prioritizing exports. Hence, statement 3 is not correct.

95. Answer C
- Capital expenditure has consistently increased over the last three years, showing the government's strong commitment to infrastructure growth.
  - In Budget 2025-26, capital expenditure increased to ₹15.5 lakh crore, marking a continued upward trend. Hence, statement 1 is correct.
- Effective Capital Expenditure includes both capital outlay and grants-in-aid for capital asset creation.
  - A significant portion of effective capital expenditure is not allocated to grants-in-aid for capital asset creation.
  - Direct spending on physical infrastructure projects and defense capital outlay contribute significantly. Hence, statement II is not correct

96. Answer A
- India's robust services exports have propelled the country to secure the seventh-largest share in global services exports, underscoring its competitiveness. Hence statement 1 is not correct.
- In 2024, India received an estimated $129.1 billion worth of remittances. Hence statement 2 is not correct.

93. उत्तर C
- वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान स्थिर कीमतों पर सेवाओं का निर्यात 11 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से बढ़ा। इसलिए, कथन 1 सही है।
- वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-सितंबर) में सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष पांच प्रमुख देशों में रहा। कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात भारत के सेवा निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत है। इसलिए, कथन 2 सही है।

94. उत्तर A
बोर्ड मुख्य रूप से घरेलू प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि केवल निर्यात पर। इसका उद्देश्य भारत के भीतर मखाना आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और निर्यात को प्राथमिकता देने के बजाय किसानों की आय में सुधार करना है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

95. उत्तर C
- पिछले तीन वर्षों में पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई है, जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - बजट 2025-26 में, पूंजीगत व्यय बढ़कर ₹15.5 लाख करोड़ हो गया, जो निरंतर ऊपर की ओर रुझान को दर्शाता है। इसलिए, कथन 1 सही है।
- प्रभावी पूंजीगत व्यय में पूंजीगत परिव्यय और पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण के लिए अनुदान सहायता दोनों शामिल हैं।
  - प्रभावी पूंजीगत व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण के लिए अनुदान सहायता के लिए आवंटित नहीं किया जाता है।
  - भौतिक अवसंरचना परियोजनाओं और रक्षा पूंजी परिव्यय पर प्रत्यक्ष व्यय महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए, कथन II सही नहीं है

96. उत्तर A
- भारत के मजबूत सेवा निर्यात ने देश को वैश्विक सेवा निर्यात में सातवीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए प्रेरित किया है, जो इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

97. Answer C

- As a percentage of GDP, the corporate bond market is only 18 percent in India, as opposed to 80 percent in Korea and 36 percent in China. Hence statement 1 is correct.
- An overwhelming majority of corporate bond issuance happens through the route of private placement, which actively deters the participation of retail investors. In FY24, the public placement of corporate bonds stood at ₹19,000 crore against the private placement of around ₹8,38,000 crore. Hence statement 2 is correct.

98. Answer D

- It is being operated under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti. Hence, statement 2 is correct.
- The program is being implemented by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) and its state counterpart organizations i.e., State Program Management Groups (SPMGs). Hence, statement 1 is correct.
- In phase 2 of Namami Gange Programme (2021-26), the states will focus on expeditious completion of projects and preparation of bankable Detailed Project Report (DPR) for projects in Ganga tributary towns, cutting down delays. Hence, statement 3 is correct.

99. Answer A

A reading above 50 on the PMI indicates expansion in the manufacturing sector, while a reading below 50 indicates contraction. Hence, statement 2 is not correct.

100. Answer B

System for Assessment, Awareness, and Training for Hospitality Industry (SAATHI) was launched by Ministry of Tourism in association with the Quality Council of India to restrict any further transmission of the virus while providing accommodation and other services post-lockdown. Hence, statement 1 is not correct and statement 2 is correct.

97. उत्तर C

- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार केवल 18 प्रतिशत है, जबकि कोरिया में 80 प्रतिशत और चीन में 36 प्रतिशत है। इसलिए कथन 1 सही है।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने का एक बड़ा हिस्सा निजी प्लेसमेंट के माध्यम से होता है, जो खुदरा निवेशकों की भागीदारी को सक्रिय रूप से रोकता है। FY24 में, कॉर्पोरेट बॉन्ड का सार्वजनिक प्लेसमेंट लगभग ₹8,38,000 करोड़ के निजी प्लेसमेंट के मुकाबले ₹19,000 करोड़ था। इसलिए कथन 2 सही है।

98. उत्तर D

- यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। इसलिए, कथन 2 सही है।
- कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एसपीएमजी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसलिए, कथन 1 सही है।
- नमामि गंगे कार्यक्रम (2021-26) के दूसरे चरण में, राज्य परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और गंगा की सहायक नदियों के शहरों में परियोजनाओं के लिए बैंकेबल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे देरी कम होगी। इसलिए, कथन 3 सही है।

99. उत्तर A

PMI पर 50 से ऊपर का अंक विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन को दर्शाता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

100. उत्तर B

आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली (साथी) को पर्यटन मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से लॉकडाउन के बाद आवास और अन्य सेवाएं प्रदान करते समय वायरस के किसी भी आगे के संचरण को प्रतिबंधित करने के लिए लॉन्च किया था। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations